● वर्ष-2
● अंक-270
रायपुर, मंगलवार
04 जुलाई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

महाराष्ट्र की दलबदल राजनीति पहुंची विधानसभा

दोनों ही गुटों से सात याचिकाएं मिली, स्पीकर बोले- गुण-दोष पर गौर करके लूंगा फैसला

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सोमवार को कहा कि उन्हें राज्य में पार्टी के नेता और मुख्य सचेतक की नियुक्ति जैसे मुद्दों से संबंधित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुटों से लगभग सात याचिकाएं मिली हैं। शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र के स्पीकर को एक पत्र भी सौंपा है जिसमें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए नौ बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाओं पर बोलते हुए स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि मुझे दोनों पक्षों से अभ्यावेदन मिले हैं, लेकिन अभी उनका अध्ययन करना बाकी है।

नार्वेकर ने कहा कि मुझे सभी याचिकाओं को सत्यापित करना होगा और उनकी सामग्री की जांच करनी होगी, जिसके बाद मैं कुछ भी कह सकूंगा। मुझे यह भी जांचना होगा कि याचिकाओं में किए गए दावे उचित हैं या नहीं। शरद पवार खेमे द्वारा दायर अयोग्यता याचिका के बारे में विशिष्ट सवालों पर, राहुल नार्वेकर ने कहा, एक प्रक्रिया निर्धारित है। मैं उस याचिका की खूबियों पर गौर करूंगा और जांच करूंगा कि वे प्रक्रियात्मक रूप से अनुपालन करते हैं या नहीं, फिर मैं इसका पालन करूंगा।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने शिवसेना के विभाजन पर

एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए, शिवसेना विधायक भरत गोगावले को पार्टी के मुख्य सचेतक और एकनाथ शिंदे को विधानसभा में पार्टी के नेता के रूप में पहचानने के स्पीकर के फैसले को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद स्पीकर कार्यालय ने सबसे पहले अजित पवार और शरद पवार खेमे के बीच एनसीपी के असली गुट की पहचान करने का फैसला किया है. यह प्रक्रिया पार्टी के संविधान के अनुरूप की जायेगी।

हमारा हिंदुत्व मुस्लिम विरोधी नहीं: फडणवीस

उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि सत्तारूढ़ शिवसेना-भाजपा गठबंधन की हिंदुत्व की विचारधारा मुस्लिम विरोधी या किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसकी विचारधारा तुष्टीकरण विरोधी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से नाता तोड़ने के बाद तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे की आलोचना की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन से पहले एएनआई संपादक स्मिता प्रकाश के साथ एक साक्षात्कार में, फडणवीस ने कहा था, हमारे लिए हिंदुत्व क्या है? हमारा हिंदुत्व मुस्लिम विरोधी या किसी समुदाय विरोधी नहीं है। हमारा हिंदुत्व तुष्टीकरण विरोधी है।

देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि किसी को खुश मत करो। सभी एक हों और अल्पसंख्यकों को शिक्षा और व्यवसाय का अधिकार हो। उनके लिए एक सिस्टम लाएँ लेकिन वोट बैंक की राजनीति न करें। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू में कैलेंडर प्रकाशित करना कोई छोटी बात नहीं है। जिसने भी शिव सेना को देखा है और जो भी इसके बारे में जानता है, उसके लिए यह बहुत बड़ी बात है। यह परिवर्तन की तरह है।

प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार को बताया अपना गुरु

मुंबई। अजित पवार के बड़े विद्रोह में शामिल हुए वरिष्ठ राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार को अपना गुरु बताया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि राकांपा पार्टी प्रमुख शरद पवार उनके गुरु हैं और वह आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनका आशीर्वाद लेंगे। राकांपा के कार्यकारी अध्यक्ष पटेल इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या वह आज शरद पवार से मिलेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शरद पवार मेरे गुरु हैं और हमेशा रहेंगे। मैं उनका आशीर्वाद लूंगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राजनीतिक

उथल-पुथल तेज हैं। अजित पवार ने शिंदे-भाजपा सरकार में शामिल होना सही समझा और उपमुख्यमंत्री बने हैं। प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने शरद पवार को धोखा दिया है, तो पटेल ने अपनी कार की खिड़की खोली और चले गए। वहीं, संवादतादा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमारी उनको हाथ जोड़कर विनती है कि पार्टी के बहुसंख्यक वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की इच्छा का वे आदर करें। उनका आशीर्वाद हम पर और पार्टी पर हमेशा बना रहे। रविवार को, शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष के दिशानिर्देशों को त्यागने और गलत रास्ता अपनाने के लिए अपने करीबी सहयोगी प्रफुल्ल पटेल और पार्टी नेता सुनील तटकरे पर निशाना साधा।

इन दिनों ✍ जय प्रकाश पाराशर

टीएस बाबा को उपमुख्यमंत्री बनाने की राजनीति

त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव यानी टीएस बाबा ने आखिर चुनाव से चार माह पहले डिप्टी सीएम पद स्वीकार कर लिया। निश्चित ही हाईकमान के साथ उनकी कोई गंभीर बात हुई होगी। अन्यथा वह वैराग्य की मुद्रा में आ गए थे। कांग्रेस को भी लगा होगा कि सरगुजा की 24 सीट पर अगर इंजिन बैठ गया तो जहाज आसमान में उड़ाए रखना मुश्किल है। सिंहदेव अगर डी शिवकुमार की तरह रहे होते तो साढ़े चार साल भी पूरी ठसक से गुजारते। टीएस बाबा के बारे में आमतौर पर लोगों में यही धारणा (परसेप्शन) है कि वह सरगुजा के राजपरिवार से आते हैं। काफी धनी-मानी व्यक्ति हैं। उनके पिता मदनेश्वर शरण सिंह देव मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे। वह अर्जुन सिंह के परम मित्र थे। उनकी मां देवेंद्र कुमारी सिंहदेव स्थापित नेता थीं। उनकी बहन आशा सिंह भी हिमाचल की बड़ी नेता हैं। लिहाजा जो उन्हें नहीं जानते, वे निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वह किसी बड़े महल में रहते होंगे, जहां बहुत सारे दरबान खड़े होंगे। उन तक पहुंचना मुश्किल काम होगा। छत्तीसगढ़ में समाजवादी आंदोलन भी काफी प्रभावी रहा और समाजवादी लोग राजपरिवारों के खिलाफ आग उगलते आए हैं। राजनीति में भी टीएस सिंह देव की जब भी मुखालिफत की गई तो उन्हें राजपरिवार का सदस्त कहकर नकारात्मक छवि बनाने के प्रयास हुए। अपनी सहजता और सरलता का राज एक बार टीएस ने खुद बताया। उनका कहना था कि उनके पिता मध्य प्रदेश के बड़े अफसर थे। छत्तीसगढ़ तो उन दिनों मध्य प्रदेश में ही हुआ करता था। लेकिन जब वह अपने पिता के साथ दौरों पर निकलते तो लोग हाथ देकर उनकी गाड़ी को रोकते। आदिवासी उन्हें रोकते। उनके पिता चीफ सेक्रट्री होते हुए भी उन लोगों के पास रुकते, उनकी बातें सुनते और जो भी मदद संभव होती, वह करते थे। इस तरह टीएस देखते कि उनके पिता सबसे कमजोर आदमी को भी कितना महत्व देते। यहीं से टीएस में सरलता के इस गुण ने जन्म लिया। वह सरलता आज भी बरकरार है। पढ़ने के लिए वह जो किताबें चुनते हैं, वे भी असाधारण होती हैं। जब वह नेता प्रतिपक्ष थे, वह अमेरिका के जाने माने बायोलाजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी एक पुस्तक पढ़ रहे थे। मैं हैरान रह गया। मेरे लिए यह कल्पना से परे है कि जमीनी राजनीति में सक्रिय कोई व्यक्ति ऐसे वैज्ञानिक रुझान का संवर्द्धन करना जानता हो। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जुगलबंदी ने कांग्रेस को असाधारण जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की थी, यह एक ऐसा तथ्य है कि भूपेश बघेल का सबसे कट्टर समर्थक भी नकार नहीं सकता। अजित जोगी इन दोनों के मुखर विरोधी थे। दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि अजित जोगी को कांग्रेस से बाहर निकाले बिना, कांग्रेस को सत्ता में नहीं लाया जा सकता। इसलिए जैसे ही अजित जोगी के बेटे अमित जोगी ने एक बड़ी गलती की, दोनों ने मौका चूका नहीं। जोगी ने एक अलग पार्टी बनाई, जो भाजपा को मिलने वाले 7 प्रतिशत वोट झटक ले गई। कांग्रेस असाधारण जनमत से सत्ता में आ गई। सरकार बनने के बाद दोनों की जुगलबंदी जैसे 180 डिग्री पर घूम गई थी। सिंहदेव के समर्थक या तो खुले समर्थन से बच रहे थे या अपने आपको विपक्ष की तरह समझने लगे थे। चुनाव के ठीक पहले कुमारी शैलजा के छत्तीसगढ़ आने के बाद कांग्रेस को अहसास हुआ होगा कि धरातल का कुछ हिस्सा खिसका है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि असंतोष को रोका जाए। सिंहदेव को भी राजनीतिक वैराग्य से बचाने के प्रयास जरूरी लगे होंगे। उत्तर तलाशने योग्य सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि उप मुख्यमंत्री बनाना एक प्रतीकात्मक समारोह है या कागजी खानापूरी है या अधिकारों के बंटवारे का समझौता है। यह तय है कि उत्तर के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

नौकरी के बदले जमीन घोटाले में चार्जशीट दाखिल

■ **लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, तेजस्वी का भी नाम**

पटना। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कंपनियों समेत कई अन्य लोगों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित

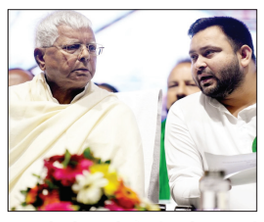

मामले में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और कई अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।

सीबीआई ने अपने विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता डीपी सिंह के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि पहले से ही आरोप पत्र दायर होने के बावजूद मामले में एक नया आरोप पत्र दायर किया गया है क्योंकि कथित कृत्य एक अलग कार्यप्रणाली के साथ किया गया है। अदालत को यह भी बताया गया कि लालू और तीन अन्य के खिलाफ मंजूरी का इंतजार है। आरोपपत्र दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई पहले से ही 12 जुलाई को होनी है। मई में इस मामले में सीबीआई ने कई राज्यों में राष्ट्रीय जनता दल की विधायक किरण देवी और राज्यसभा सदस्य प्रेम चंद गुप्ता से संबंधित नौ ठिकानों पर छापेमारी की थी।

यह कदम उन अटकलों के बीच आया है कि जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में लौट सकते हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि जस्वी यादव ने तो खुद कहा था कि चार्जशीट में उनका नाम आएगा। अभी जिस तरह का माहौल है और भाजपा जैसी राजनीति कर रही है।

मुख्यमंत्री द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को सेन्ट्रल इंडिया रीजनल कांउसिल की रायपुर शाखा द्वारा आयोजित दो दिवसीय सी.ए विद्यार्थियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आंमत्रण दिया।

प्रमुख समाचार

समान नागरिक संहिता को संविधान में सरकार का कर्तव्य बताया गया: आरिफ मोहम्मद

नई दिल्ली। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी)

पर पीएम मोदी के जोर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है, हालांकि देर हो चुकी है लेकिन कभी नहीं से देर बेहतर है। वह जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसे (यूसीसी) संविधान में सरकार का कर्तव्य बताया गया है। लोग कहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय धर्मग्रंथ हमारा संविधान है तो फिर समान नागरिक संहिता का विरोध क्यों? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इससे पहले भी लगातार समान नागरिक संहिता पर अपनी राय रखते नजर आए हैं। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हिंदू कोड बिल को अब 7 दशक से ज्यादा समय हो गया है। केरल के राज्यपाल ने कहा कि यह हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों पर समान रूप से लागू होता है। क्या वह उन सभी के बीच एकरूपता पैदा करने में सक्षम है?

पहली बार 65 हजार के पार बंद हुआ सेंसेक्स

मुंबई। शेयर बाजार में सोमवार को बंपर खरीदारी दिखी और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया। सेंसक्स 486.49 अंक यानी 0.75 फीसदी चढ़कर 65,205.05 अंक पर बंद हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है, जब सेंसेक्स ने 65 हजार का आंकड़ा पार कर बंद हुआ है। वहीं, निफ्टी भी रिकॉर्ड अंकों पर बंद हुआ है। निफ्टी 133.50 अंक यानी 0.70 फीसदी बढ़कर 19,322.55 पर बंद हुआ। बाजार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाने में बड़ा योगदान हैवीवेट शेयरों में बढ़ी खरीददारों की दिलचस्पी, मेटल सेक्टर के शेयरों का रहा। बुधवार के कारोबारी सत्र के पहले तीन सत्रों में निवेशकों को 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फायदा हुआ। मानसून की शुरुआत, एचडीएफसी बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प के विलय पूरा करने की घोषणा व जून डेरिवेटिव श्रृंखला की समाप्ति से बाजार को इस रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने में मदद मिली। अमेरिकी बाजार में हुई रैली से भी निवेशकों में सकरात्मक माहौल का भी बाजार को फायदा मिला। इसके चलते सभी सेक्टर हरे निशान पर रहे। साल के अंत तक निफ्टी 21,000 के स्तर को छू सकता है। इसी तरह सेंसेक्स में भी बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती

जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। एक नोटिस के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने मामले को उठाया और मामले को सुनवाई के लिए तैयार करने के लिए प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किए। जम्मू-कश्मीर का %विशेष दर्जा% छीनने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए 20 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि निर्णय लेते समय संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

रालोद के भाजपा से हाथ मिलाने का दावा गलत-जयंत

बागपत (उप्र)। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) प्रमुख जयंत चौधरी ने महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हाथ मिलाने की अटकलों को खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि उनका रुख बिल्कुल स्पष्ट है और वह विपक्षी दलों की अगली बैठक में जरूर शामिल होंगे। चौधरी ने यहां एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा से हाथ मिलाने की अटकलों और दावों को गलत बताया। चौधरी का रालोद समाजवादी पार्टी (सपा) का सहयोगी दल है और उसने वर्ष 2022 का उ?तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था। चौधरी सपा की मदद से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। चौधरी से पूछा गया था कि के-?द्रीय मंत्री रामदास अठावले और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अ?यक्ष ओमप्रकाश राजभर कह रहे हैं कि महाराष?ट्र में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद वह (चौधरी) भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। उन?होंने कहा, मेरा रुख बिल?कुल स्पष्ट है। उनके (अठावले और राजभर) कहने से क?या होता है। रालोद अ?यक्ष ने कहा कि 23 जून की बैठक के बाद विपक्षी दलों की अगले दौर की जो बातचीत होगी उसमें वह शामिल होंगे।

खालिस्तान के धमकी भरे पोस्टर पर जयशंकर की चेतावनी, आपसी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं...

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कनाडा को खालिस्तानी तत्वों को जगह देने के खिलाफ चेतावनी दी। जयशंकर का बयान यह सामने आने के बाद आया कि कनाडा में खालिस्तानी धमकी वाले पोस्टरों में भारतीय राजनयिकों के नाम थे।

जयशंकर ने कहा कि भारत ने खालिस्तानी पोस्टरों में भारतीय राजनयिकों की तस्वीरों का मुद्दा कनाडाई अधिकारियों के समक्ष उठाया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे साझेदार देशों से संपर्क किया है और उनसे खालिस्तानी समूहों को जगह नहीं देने का अनुरोध किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे देशों के बीच संबंधों पर असर पड़ेगा। विदेश मंत्री ने भाजपा के आउटरीच अभियान के मौके पर संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि हमने कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने साझेदार देशों से, जहां कभी-कभी खालिस्तानी गतिविधियां होती हैं। खालिस्तानियों को जगह न देने का अनुरोध किया है।

शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी के नेताओं के खिलाफ चल रहे केस,

शिवेंद्र तिवारी

महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को बड़ा उलटफेर हुआ। अजित पवार सहित एनसीपी के नौ विधायक एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए। अब इस गठबंधन को महायुति नाम दिया है जिसमें भाजपा, शिवसेना और एनसीपी (अजित गुट) शामिल हैं। इसके बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि ये नेता ईडी-सीबीआई के मामलों की वजह से भाजपा के साथ आए हैं। एनडीए में शामिल एनसीपी के इन नेताओं में कई ऐसे हैं जो खुद या उनके परिजन के खिलाफ अलग-अलग मामले चल रहे हैं।

अजित पवार

अजित पवार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ऋणों में अनियमितताओं के आरोपों पर आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच का सामना कर रहे थे। इसके आधार पर, ईडी ने भी इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए मामला दर्ज किया। सितंबर 2020 में, ईओडब्ल्यू ने कहा कि उसे किसी भी आपराधिक गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला और विशेष अदालत के समक्ष एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की। ईडी ने 2020 में ईओडब्ल्यू के रुख का विरोध किया था लेकिन विशेष अदालत ने उसके हस्तक्षेप को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अगर ईओडब्ल्यू केस बंद हो जाता तो ईडी भी जांच जारी नहीं रख सकती। इससे पहले कि विशेष अदालत ईओडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला कर पाती, जून 2022 में राज्य में एनडीए की सरकार आ गई। इसके साथ, ईओडब्ल्यू ने भी अक्तूबर 2022 में अपना रुख बदल दिया और कहा कि वह अपनी क्लोजर रिपोर्ट को अलग रखते हुए जांच जारी रखना चाहता है। फिलहाल, ईओडब्ल्यू की जांच जारी है और राज्य की एजेंसी ने अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है।

इस बीच, ईडी ने अप्रैल में अपनी जांच में आरोप पत्र दायर किया। बैंक में और बैंक से ऋण लेने वाली चीनी सहकारी समितियों को खरीदने वाली कुछ कंपनियों में अजित की भूमिका का ईडी के आरोप पत्र में उल्लेख किया गया था, लेकिन अजित को मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।

हसन मुश्रीफ

हसन मुश्रीफ सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों के कामकाज में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में मुंबई में ईडी की तलाशी का सामना कर रहे। मुंबई की विशेष अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अपनी दलीलों में मुश्रीफ ने कहा था कि उनके खिलाफ मामला एक प्रेरित साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें ईडी मामलों में शामिल करने का जानबूझकर प्रयास किया गया। मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका अप्रैल में विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का

दरवाजा खटखटाया। पिछले हफ्ते अदालत ने उनकी अंतरिम राहत 11 जुलाई तक बढ़ा दी।

छगन भुजबल

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भुजबल और 16 अन्य के खिलाफ 2006 में तीन परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक के ठेके देने में कथित अनियमितताओं के आरोप में 2015 में मामला दर्ज किया गया था। भुजबल तब राज्य के मंत्री थे। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक अलग मामला भी दर्ज किया गया था। एजेंसी ने मामले में भुजबल को गिरफ्तार किया और दो साल जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। सितंबर 2021 में एक विशेष अदालत ने भुजबल और अन्य को बरी कर दिया। भुजबल के खिलाफ ईडी मामले के अलावा मुंबई विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार मामले के संबंध में एसीबी द्वारा दायर एक मामला एक विशेष अदालत के समक्ष लंबित है।

सुनील तटकरे

महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में अदिति तटकरे शामिल हैं। सिंचाई घोटाले में अजित पवार के अलावा अदिति के पिता सुनील तटकरे की भी एसीबी जांच कर रही है। 2017 में एसीबी द्वारा दायर आरोपपत्र में, उसने तटकरे के नाम का उल्लेख किया था। हालांकि उस समय आरोपी के रूप में उनका नाम नहीं आया। अधिकारियों ने कहा था कि बाद में अलग से आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। ईडी ने इसी मामले के सिलसिले में 2012 में तटकरे के खिलाफ प्रारंभिक जांच भी शुरू की थी।

प्रफुल्ल पटेल

ईडी ने 2019 में आरोप लगाया था कि प्रफुल्ल पटेल से जुड़ी एक कंपनी ने 2006-07 में वर्ली में सीजे हाउस बनाया था और इसकी दो मंजिलें 2007 में दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मेमन उर्फ मिर्ची की पत्नी को हस्तांतरित कर दी गई थीं। मिर्ची के परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ दायर मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पटेल को 2019-2021 के बीच तलब किया गया। जुलाई 2022 में ईडी ने सीजे हाउस की चार मंजिलें कुर्क कर ली गईं। एनसीपी नेता ने मिर्ची के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया था। ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र में प्रफुल्ल को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कबाड़ माफिया की चुनौती

■ बिजली के खम्भों को काटकर उठा लिया, पहाड़ी कोरबा मॉडल गांव की उम्मीद टूटी

कोरबा। बालकोनगर पुलिस ने बिजली के खम्भों को काटकर चोरी करने वाले गिरोह के कुछ लोगों को आज गिरफ्तार किया है। लेकिन यह कोई सामान्य समाचार नहीं है। बिजली के खम्भों को काटना एक असामान्य घटना है। क्योंकि बिजली विभाग के मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं हैं। यानी कबाड़ माफ्रिया का हौसला इतना बुलन्द है कि उसे मुख्यमंत्री के विभाग पर हाथ डालते हुए भी कोई डर नहीं लगा? कबाड़ माफ्रिया ने यह दुस्साहस कहां से जुटाया? कि परोक्ष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनौती दे डाली!

जिले में सक्रिय कबाड़ माफ्रिया का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विभाग को भी नहीं बख्श रहा है। बीते एक पखवाड़े के भीतर कोरबा ब्लाक के छातासराई गांव तक बिजली आपूर्ति के लिए लगाए गए लोहे के 31 खम्भों को काटकर चोरी कर लिया गया। राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा जनजाति का एक पुनर्वास ग्राम है छातासराई। माखुरपानी पंचायत के इस गांव में बिजली आपूर्ति के लिए विद्युत मण्डल ने लोहे के खम्भे लगाकर बिजली की लाइन बिछाई थी। बीते गुरुवार 22 जून 2023 को ट्रक लेकर पहुंचे कबाड़ माफ्रिया ने गैस कटर से 19 खम्भे काट लिए और उठा ले गया। माखुरपानी के सरपंच बहुरनसिंह के अनुसार घटना की जानकारी दूसरे दिन

सुबह हुई।

आपको बता दें कि बालको नगर थाना क्षेत्र के पर्यटन स्थल सतरेंगा पहुंच मार्ग पर ग्राम पंचायत माखुरपानी का आश्रित गांव छातासराई एक पहाड़ पर बसा है। पांच साल पहले इस पहाड़ी कोरवा गांव को जिला प्रशासन ने मॉडल गांव के रूप में विकसित किया था। गांव में बिजली व्यवस्था के लिए 40 लाख की लागत से पहाड़ के नीचे से लेकर ऊपर तक बिजली के खंभे लगा कर केबल के माध्यम से गांव तक बिजली पहुंचाई गई थी। कुछ दिन तक बिजली चालू रहने के बाद से आपूर्ति बंद हो गई थी। कबाड़ चोरों ने लाइन के बंद रहने का फायदा उठाया। पहले तो कई जगह से केवल को काटकर ले गए। फिर गुरुवार की रात 19 खंभों को भी गैस कटर से काटकर ले गए। इस घटना के बाद बिजली के 12 खम्भे शेष रह गए थे। कबाड़ माफ्रिया ने सोमवार 26 जून की रात छातासराई में दोबारा धावा बोला और इन 12 खम्भों को भी काट ले गया। खास बात यह है कि इसी दिन विद्युत वितरण विभाग के अधिकारी कथित रूप से छातासराई गांव पहुंचे थे।

यहां उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का प्रभार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वयं के पास है। बिजली के खंभों को इस तरह से काटकर उठा ले जाना एक तरह से मुख्यमंत्री के लिए चुनौती ही कहा जाएगा। इससे पहले कोरबा से राजगामार तक एसईसीएल की रेल लाइन एक बड़े हिस्से को कबाड़ माफ्रिया निकालकर ले जा रहा था तब ग्रामीणों ने कबाड़ चोरों को पकड़ कर राजगामार पुलिस चौकी को पिछले दिनों सौंपा था और पुलिस चौकी में प्रदर्शन किया था। दूसरी ओर एसईसीएल के सूराकछार से हसदेव ताप विद्युत गृह तक वर्षों पूर्व बिछाई गई रेल लाइन के एक बड़े हिस्से को भी कबाड़ माफ्रिया काटकर उठा ले गया है। पिछले दिनों तुलसी नगर कोरबा में भी बिजली के कई खम्भे काट लिए गए थेए लेकिन इन्हें कबाड़ माफ्रिया उठा पाता इससे पहले ही विभाग को जानकारी मिल गई और खम्भे के टुकड़ों को सुरक्षित कर लिया गया था। इसके अलावा एसईसीएल की सभी खदानों से पिछले कुछ दिनों में करोड़ों रुपयों के स्क्रैप और भारी वाहनों के कल पुर्जों की चोरी की खबर भी है हालांकि इनमें से कितने मामलों की रिपोर्ट पुलिस में दी गई हैघ् यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

ज्ञात हो कि कबाड़ चोर गिरोह ने ग्राम छातासरई रोड में बिजली खम्भे को गैस कटर से काट कर मनीष पटेल के 407 माजदा वाहन क्रमांक सीजी 12 9698 में बिजली के 11 नग खम्भे को 3.3 टुकडो में काटकर माजदा वाहन में लोड किया था। अधिक वजन होने से वाहन कीचड़ में फस गया था जो नही निकलने से दूसरा वाहन मंगाकर चोरी किये लोहे के खम्भे को ले गए थे। आरोपियो से एक टाटा कंपनी के 407 माजदा वाहन क्रमांक सीजी 04 जेबी 4904 में भरा हुआ 33 नग लोहे की खम्भा का टुकड़ाए 3 नग आक्सीजन सिलेण्डर, लोहे का कास आर्म स्टे तार एवं एन्सुलेटर लगभग 300000 रू एवं घटना स्थल से माजदा वाहन क्रमांक सी जी 12/ 9698 जप्त किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले कटे गए खम्भे कहां हैं? उन्हें कहां बेचा गया है? चोरी के स्क्रेप का खरीददार कौन है? कबाड़ चोरों का सरगना कौन है? क्या जिला पुलिस इस कबाड़ माफ्रिया को कानून के कटघरे में खड़ा कर पायेगा? इस सभी सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है।

आपको बता दें कि जिले में इससे पहले कभी भी किसी कबाड़ गिरोह ने इतना बड़ा दुस्साहस नहीं किया था, जितना इन दिनों हो रहा है। एस ई सी एल की खदानों से प्रतिदिन लाखों रुपयों के कोयला, डीजल और कबाड़ चोरी की घटनाएं आम हो गई हैं। एस ई सी एल प्रबन्धन और खदानों की सुरक्षा के लिए तैनात सी आई एस एफऔर त्रिपुरा रायफल्स के जवान इन घटनाओं को रोकने में विफल क्यों हैं? यह केंद्रीय एजेंसियों का जांच का विषय हो सकता है।

मुख्यमंत्री बघेल ने किया नगर निगम चिरमिरी में यूपा का वर्चुअल उद्घाटन

मनेंद्रगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूपा योजना का वर्चुअली लोकार्पण किया। एमसीबी ज़िले में जिलास्तरीय कार्यक्रम नगर निगम चिरमिरी के सभागार में आयोजित किया गया।महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क यूपा अर्थात् अर्बन आजीविका पार्क योजना के क्रियान्वयन हेतु नगर पालिक निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 01 चित्ताझोर पोड़ी में कुल 1.51 हेक्टेयर (3.1 एकड़) में स्थापित किया जा रहा है, जिसमें कुल 6 संभावित गतिविधियाँ (फ़र्म, एसएचजी, उद्यम) प्रारंभ करने से 25 महिलाओं और 50 पुरुषों को मिलाकर लगभग 75 लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा।इसी तरह मनेंद्रगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में भी शीघ्र ही यूपा प्रारंभ किया जाएगा।मनेंद्रगढ़ नगरपालिका में भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा मितान योजना का विस्तार किया गया। नई लेदरी और झगराखंड के लिये एक एमएमयू प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉ. विनय जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा नगर निगम चिरमिरी को यूपा का सौग़ात दिया गया है। यूपा के माध्यम से स्थानीय युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। दूर-दराज के लोगों को भी निगम क्षेत्र में यूपा प्लेटफ़ॉर्म दिया जायेगा जिससे स्वरोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।नये ज़िले के निर्माण से पूरे क्षेत्र को लाभ हो रहा है।मितान योजना के विस्तार और नये एमएमयू के संचालन से नागरिकों को लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। जनता के हितों को ध्यान में रखकर योजना बनाने वाले जनहितैषी सरकार को धन्यवाद।

हसदेव अरण्य के सरपंचों से मिले महंत

■ सालों से चल रही है जल जंगल जमीन की लड़ाई

कोरबा। कटघोरा प्रवास पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से हसदेव अरण्य क्षेत्र के सरपंचों ने मुलाकात की। इस क्षेत्र के कोल ब्लॉक प्रभावित ग्रामों के सरपंचों ने कटघोरा के रेस्ट हाउस में महंत से मुलाकात कर अपनी बात रखी। विधानसभा को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रभावितों गांव के सरपंच व ग्रामीण मदनपुर क्षेत्र में कॉल ब्लॉक का लंबे समय से विरोध कर रहे हैं।

500 दिनों से चल रहा है आंदोलन

ग्रामीण ने डॉ महंत से कहा कि वह किसी स्थिति में हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक नहीं खुलने देना चाहते। जिसके लिए क्षेत्र के ग्रामीण पिछले 500 दिनों से आंदोलनरत हैं। कोल ब्लॉक के लिए सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना को रद्द करते हुए सम्पूर्ण हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाया जाए। इस क्षेत्र में परसा, मदनपुर साउथ, पतुरिया गिदमुड़ी और केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक प्रस्तावित हैं। कोरबा और सरगुजा जिले के बड़े वन क्षेत्र को निकाला जाएगा। इसके लिए राज्य व केंद्र सरकारों ने अनुमति दी है। कोयला उत्खनन का ठेका निजी कंपनियों को दिया गया है। सरपंचों ने मांग की कि ग्रामीणों को अधिकार पट्टा आवंटित नहीं हुए हैं। इस दिशा में भी कदम उठाया जाए। हसदेव अरण्य क्षेत्र के 8 गांव के सरपंचों के प्रतिनिधित्व समूह ने कोल ब्लॉक के लिए फर्जी ग्राम सभा की निष्पक्ष जांच की मांग भी की। हसदेव में सभी कोयला खदानों को रद्द करने के विधानसभा के अशासकीय प्रस्ताव के बावजूद अब तक परसा खदान की वन स्वीकृति निरस्त न किए जाने से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा कर अपनी बात रखी।

महंत ने वन अधिकार पट्टा पर दिया आश्वासन -

विधानसभा अध्यक्ष ने कोयला ब्लॉक के अधीन आने वाले वन क्षेत्रों की जानकारी ली। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान उनके साथ क्षेत्रीय कांग्रेसी विधायक मोहित केरकेट्टा, डीएफओ प्रेमलता यादव भी मौजूद रहे। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान डॉ महंत ने वन अधिकार पट्टा संबंधी मामलों के निराकरण की बात कही। ग्रामीणों को यथासंभव मदद देने का आश्वासन भी दिया।

इन गांवों के सरपंच रहे मौजूद

विधानसभा अध्यक्ष डा। चरणदास महंत से मुलाकात के दौरान उमेश्वर आर्मो सरपंच पतुरियडांड, अमृतलाल के सरपंच गिधमुड़ी, देव साय मरपच्ची सरपंच मदनपुर, धन साय मंझवार सरपंच धजाक, जयसिंह बिंझवार सरपंच सिल्ली, ठंडीलाल सरपंच अरसियां, रमेश मंझवाई सरपंच केंदई, आनंद राम कुसरो सरपंच सालरी ग्राम, मुंशी प्रसाद पोर्ते सदस्य सालरी ग्राम, भुनेश्वर फत्तेपुर, बिपाशा पाल पर्यावरण कार्यकर्ता रायपुर, डा। ऋषिकांत चौधरी शोधार्थी मदनपुर, विजय कुमार कोर्राम सरपंच सालरी ग्राम, जयवर्धन पोर्ते सरपंच घाटबर्रा उपस्थित रहे।

पुलिस इंस्पेक्टर की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। जिसके तहत कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामला और विभागीय जांच एक साथ नहीं किया जा सकता है। बिलासपुर के पुलिसकर्मी राजेंद्र यादव ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। पुलिस इन्सपेक्टर की याचिका पर कोर्ट ने मामले में विभागीय जांच पर स्टे देकर याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी है। यह केस बिलासपुर के पुलिसकर्मी राजेंद्र यादव से जुड़ा हुआ है। वह दुर्ग में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। इस दौरान उनकी ड्यूटी के दौरान एक महिला ने शिकायत की थी। जिस पर अमलेश्वर थाने में एक आपराधिक केस दर्ज किया गया था। जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने चालान प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान ही उनके खिलाफदुर्ग एसपी ने विभागीय जांच शुरू कर दी। इस डिपार्टमेंटल जांच से परेशान होकर इंस्पेक्टर राजेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर फैसला आया है। इस केस में याचिकाकर्ता की तरफसे वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एमपॉल एन्थनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड और अन्य मामलों में यह सिद्धान्त लागू नहीं किया गया है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफआपराधिक केस दर्ज किया गया है और संबंधित विभाग द्वारा समान आरोपों पर विभागीय जांच की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। दोनों मामलों में अगर गवाह सेम है। तो ऐसी स्थिति में आपराधिक मामले में गवाहों का बयान सबसे पहले लिया जाना चाहिए। अगर विभागीय जांच कार्रवाई में सभी गवाह से सबूत और गवाही ले ली जाती है तो इससे कोर्ट में चल रहे मामले में असर पड़ेगा। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने राजेंद्र यादव को राहत दी है। विभागीय जांच पर स्टे लगा दिया गया है।

राजस्व मंत्री ने किया एसईसीएल कॉलोनियों का दौरा, साफ सफाई की खुली पोल

कोरबा। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एसईसीएल कोरबा एरिया के अस्पताल और कॉलोनियों का सोमवार को दौरा किया। मंत्री ने इस दौरान देखा कि यहां के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है।राजस्व मंत्री के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और एसईसीएल के अधिकारी भी मौजूद थे।

कॉलोनियों में बदइंतजामी- अपने दौरे के दौरान मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने देखा की कॉलोनियों में अव्यवस्था है। कॉलोनी में रहने वालों ने भी मंत्री से शिकायत की कि यहां समस्या बताने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। लोगों की शिकायत के बाद मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने काम न होने पर ठोस कार्रवाई की बात भी कही।

जयसिंह अग्रवाल ने कहा मैंने एसईसीएल के सुभाष ब्लॉक और ऑफिसर कॉलोनी का दौरा किया। स्थिति बेहद खराब है। कुछ मकानों के छज्जे टूट कर गिर रहे हैं, लोग खतरों के बीच जीवन यापन कर रहे हैं। कहीं कचरों का ढ़ेर लगा हुआ है। लाखों रुपए की लागत से बनाया गया वाटर एटीएम आज तक शुरू नहीं हो सका है। जिसे 4 साल पहले स्थापित किया गया था। सफाई के लिए स्थापित एसएलआरएम सेंटर में भी ताला लगा हुआ मिला। ना तो यहां सफाई हो रही है, ना ही बिजली की व्यवस्था ठीक-ठाक है। ना तो पेयजल ही लोगों को मिल पा रहा है। व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि कोल इंडिया की सहायक कंपनी एसईसीएल कोरबा से अरबों रूपये का राजस्व अर्जित करती है। बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन इनकी विभागीय कॉलोनी में लोगों को मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हम पत्र लिखेंगे और जरूरत पड़ी तो आगे चलकर और भी ठोस करवाई करेंगे। गंदगी से एसईसीएल निवासी परेशान- सोमवार को मंत्री ने मुड़ापर के विभागीय अस्पताल का जायजा लिया। यहां के मरीज काफी परेशान दिखे। मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। साथ ही बिल्डिंग के मरम्मत कराने की बात कही। इसके बाद बाद मंत्री एसईसीएल के कॉलोनी में पहुंचे। यहां घूमकर मंत्री ने लोगों से बातचीत की।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

अचानकमार में बाघों की संख्या हुई 8, 2 मादा शामिल

बिलासपुर। अचानकमार टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने दावा किया है कि यहां बाघों की कुल संख्या 8 हैं, जिनमें 2 मादा हैं। एक अन्य बाघ कान्हा टाइगर रिजर्व से अक्सर आता है। अचानकमार में बाघों की संख्या को लेकर वन विभाग संदेह के घेरे में रहा है। यहां भ्रमण करने वाले पर्यटकों को प्राय: बाघ दिखते ही नहीं हैं। पर इस बार वन विभाग ने ट्रैप कैमरों में कैद तस्वीरों के जरिये बाघों की उपस्थिति को लेकर दावा किया है। इसके मुताबिक एकेटी 2 नाम की मादा बाघिन की तस्वीर 16 फरवरी, 3 मार्च, 26 मार्च, 10 मई और 27 मई को कैमरे में कैद की गई है। एक अन्य मादा एकेटी 8 5 फरवरी, 26 फरवरी, 5 मार्च, 12 मई व 19 फरवरी को देखी गई। नर बाघ एकेटी 9 को 26 फरवरी, 17 फरवरी, 20 फरवरी, 1 अप्रैल व 25 मई को कैमरे में देखा गया है। मादा एकेटी 13 को 25 फरवरी को कैमरे में देखा गया। मादा एकेटी 114 को 3 मार्च, 11 मई, 14 मई और 16 फरवरी को कैमरे में कैद किया गया। नर एकेटी 5 को 6 दिसंबर को तथा मादा एकेटी 16 को 29 मई को कैमरे में कैद किया गया।

17 से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन पंचायत स्तर पर

जगदलपुर। शासन के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक छत्तीसगढिया ओलम्पिक 2023-24 का आयोजन किया जाना है। छत्तीसगढिया ओलम्पिक आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय प्रशासन विभाग को सौंपा गया है। आयोजन हेतु विकासखण्डों, नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक राजीव युवा मिता क्लब (ग्राम पंचायत-वार्ड) में जोन व विकासखण्ड स्तर, नगरीय एवं जिला स्तर पर निर्धारित तिथियों में छत्तीसगढिया ऑलम्पिक 2023-24 का आयोजन किया जाएगा। जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर 17 से 22 जुलाई तक, जोन स्तर पर 26 जुलाई से 31 जुलाई तक, विकासखंड व नगरीय क्लस्टर स्तर पर 07 अगस्त से 21 अगस्त, जिला स्तर पर 25 अगस्त से 04 सितंबर और संभाग स्तर पर 10 सितंबर से 20 सितंबर 2023 तक आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विजय दयाराम के द्वारा जिला स्तरीय ओलम्पिक आयोजन हेतु जिला स्तरीय समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष कलेक्टर है।

बिलासपुर में अभा संत समिति का 24 सितंबर को धर्मसभा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अखिल भारतीय संत समिति 24 सितंबर को विशाल धर्मसभा का आयोजन करने जा रही है। इसमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, मतांतरण, धर्मांतरण और लव जिहाद पर अंकुश लगाने को लेकर चर्चा की जाएगी। सभा में प्रदेश के साथ ही देशभर के भारतीय संत और हिंदू संगठन के लोग शामिल होंगे। रतनपुर में अखिल भारतीय संत समिति छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है। संत समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि, प्रदेश में मतांतरण, धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसपर विचार और अंकुश लगाना आवश्यक हो गया है। यही नहीं अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और समान नागरिक संहिता की विशेषता और आवश्यकता पर भी विचार करने की आवश्यकता है। लिहाजा इसे लेकर बिलासपुर में विशाल धर्मसभा का आयोजन किया जा रहा है।

पुटू खाने से एक ही परिवार के चार लोग बीमार

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के मैनपाट विकासखंड के ग्राम परपटिया में रविवार रात जंगली पुटू के सेवन से एक ही परिवार के चार सदस्य बीमार पड़ गए। इनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। सभी को उल्टी-दस्त शुरू हो गया। इसके बाद उन्हे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमलेश्वरपूर में भर्ती कराया गया है। उपचार के बाद पीड़ितों की हालत में सुधार हुआ है। जानकारी के अनुसार, ग्राम पटपरिया निवासी एक माझी परिवार ने रविवार को जंगली पुटू की सब्जी का सेवन किया था। इसके कुछ देर बाद ही परिवार के सदस्यों को उल्टी-दस्त होने लगी। अचानक चार लोगों के बीमार पड़ जाने की सूचना पर उन्हें आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ितों में कबरी मझवार (30), फूलमती (25), मनरूपा (10) और सुमारसाय (12) शामिल है। मैनपाट बीएमओ डा.आर. एस. पैकरा ने बताया कि उपचार के बाद चारों की हालत में सुधार हुआ है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। एहतियातन सभी को फिलहाल अस्पताल में निगरानी के लिए रखा गया है और उन्हें दवाएं भी दी जा रही हैं।

योग संघ जिला सक्ती के उपाध्यक्ष बने मोहन चंद्रा

सक्ती। छत्तीसगढ़ योग शिक्षक संघ ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए श्री मोहन लाल चंद्रा जी को उनके योग के प्रति समर्पण व निष्ठा को दृष्टिगत रखते हुए जिला उपाध्यक्ष सक्ती नियुक्त किया है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल चन्द्राकर ने नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि मोहन लाल चंद्रा कबीरधाम सक्ती जिला में पहले से ही सक्रिय रूप से कार्य कर रहे है। प्रदेश महासचिव खोमेश साहू ने उक्त जिला उपाध्यक्ष को डिजिटल मनोनयन पत्र प्रेषित कर बधाई के साथ-साथ जिला उपाध्यक्ष के कार्यों, उद्देश्यों व नियमों से परिचित कराकर जिले में समर्पण भाव के साथ कार्य करने का शुभाशीष दिया है! सम्भागाध्यक्ष सत्यम तिवारी ने इसे सक्ती जिला में योग के प्रसार में एक अहम कड़ी के रूप में माना है! बिंदु सिंह, वीर तिवारी ने इसे बिलासपुर परिक्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया है! मोहन का कहना हैं कि जिला उपाध्यक्ष बनकर संघ के विकास एवं जिला में योग के प्रसार के लिए अपना सर्वस्व मेहनत देंगे।

कसडोल खंड चिकित्सा अधिकारी पर लग रहे हैं कई तरह के गंभीर आरोप

■ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई तरह के कारनामे किए हैं जो प्रपत्र में आ रहे सामने

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के कसडोल विकासखंड में जहां पर कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खंड चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं अंजन सिंह चौहान जो काफी समय से अपनी सेवाएं विभिन्न जगहों पर दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा सराहनीय कार्य को देखते हुए उन्हें राज्य सरकार से सम्मानित भी किया गया था मगर आज दिनांक में जिला कलेक्टर बलौदाबाजार के पास एक प्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें नगर पंचायत कसडोल अध्यक्ष,पार्षद, तथा नगरवासी के तरफ से एक प्रपत्र जिला कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें कई सारे पहलू पर खंड चिकित्सा अधिकारी के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप जैसे

बातें लिखी हुई है जिनमें खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंजन सिंह चौहान के विरुद्ध स्थानांतरण नीति में शासन के नियमों का उल्लंघन करने के संबंध में, एनआरसी शाखा के कर्मचारियों से अन्य शाखा की सेवाएं लेने से कुपोषित बच्चों की सेवा एवं देख भाव में प्रभाव डालने वाले अनजान सिंह चौहान के संबंध में, तथा उच्च कार्यालय विभागाध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन करने वाले डॉक्टर अंजन सिंह चौहान के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए।

संचनालय स्वास्थ्य सेवाय छत्तीसगढ़ के आदेश का उल्लंघन

उपरोक्त लेख है कि संचनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ विभाग अध्यक्ष कार्यालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ02-17/2023 विज्ञप्ति जारी कर सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश किया गया है कि शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में संलग्नीकरण समाप्त कर अधिकारी कर्मचारी को उनके मूल पदस्थापना स्थल हेतु कार्यमुक्त किया जावे जिसके परिपालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ ने जिले के सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को दिनांक 9/05/ 2023 को जारी कर संलग्नीकरण के तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए वर्तमान में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापना स्थल हेतु कार्य मुक्त कर दिया गया है संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला बलौदा बाजार भाटापारा द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि यदि अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना स्थल हेतु कार्य मुक्त कर दिया गया है संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदा बाजार भाटापारा द्वारा स्पष्ट निर्देशित है कि यदि अधिकारी कर्मचारी को उनके मूल पदस्थापना स्थल हेतु कार्यमुक्त किए जाने में लापरवाही किया जाता है तो उन पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी मगर खंड चिकित्सा अधिकारी अंजन सिंह चौहान के द्वारा इस नियमों का पूर्णत: तरह पालन नहीं किया गया।

2 माह भी नहीं टिकती सड़क की मरम्मत अर्जुंदा से नादगांव मार्ग जगह-जगह उखड़ी

बालोद। अर्जुंदा से नादगांव मार्ग पर सड़क जगह-जगह उखड़ गई है। चीरचार तक मुख्य मार्ग में किया गया डामरीकरण गुणवत्ताहीन है। दो माह मे जगह जगह दरार पड़ गई है। सड़क को जब डामरीकारण किया गया था तब पंद्रह दिन मे ही बड़े बड़े दरार पड़ गई थी। तब इसे उखाड़ कर पुन: डमरीकारण किया गया। उसके बाद दो माह में पुन: उखड़ गई। इस ओर किसी का ध्यान नहीं है।

यह सड़क ग्राम भरदाकला से बिजेभाठा के मध्य तक पूरी तरह से खराब है। हाई स्कूल के पास तो जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। सड़क के किनारे के गांव के ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क कभी भी 2 माह से ज्यादा नहीं टिकी है। जब जब इसकी मरम्मत की जाती है दो-तीन माह में उखड़ जाती है। लोगों को आश्चर्य है कि पता नहीं किस तरह से मरम्मत करते हैं कि सड़क टिकती ही नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में भारी लीपापोती की

जाती है। जबकि यह सड़क दुर्ग और राजनांदगांव जिले को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है। इस मार्ग पर दो दर्जन से ज्यादा बसें चलती है वहीं कई भारी वाहन भी चलते हैं इसके बाद भी सड़क निर्माण में गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं दिए जाने से परेशानी हो रही है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की बैठक

नईदिल्ली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की कवायद को गति देने के लिए प्रमुख विपक्षी पार्टियों की आगामी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बैठक की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, पटना में विपक्ष की सफल बैठक के बाद हम अगली बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में करेंगे। हम फासीवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों को पराजित करने तथा देश को आगे ले जाने वाले एक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के अपने संकल्प को लेकर अडिग हैं। गत 23 जून को पटना में विपक्षी दलों ने बैठक की थी जिसमें उन्होंने भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने और आगे बढ़ने को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई थी। विपक्षी दलों की अगली बैठक ऐसे समय होने जा रही है जब महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हो गई है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले से जुड़े ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इसी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार निदेशक विजय नायर, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू, (शराब कंपनी एम/एस पेरनोड रिकार्ड के प्रबंधक) की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष समेत सभी आरोपित ने चुनौती दी थी। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं।

केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पिछले 3 साल का बजट मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास विज्ञापन के लिए पैसा है। आपके पास परियोजनाओं के लिए पैसा क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त करने के लिए इसकी आलोचना की। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की दो-न्यायाधीश पीठ ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में आरआरटीएस परियोजना के विज्ञापनों पर अपने खर्च का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 21 अप्रैल 2023 को एक आदेश में दिल्ली सरकार को दस दिनों के भीतर परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था।

एकनाथ शिंदे की जगह लेंगे अजित पवार : संजय राउत

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सोमवार को दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार जल्द ही एकनाथ शिंदे की जगह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। राउत ने कहा कि शिंदे को सीएम पद से हटा दिया जाएगा और 16 बागी शिवसेना विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बता दें कि अजित पवार रविवार को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए और उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। संजय राउत ने कहा, आज मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने वाला है। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। भाजपा शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को तोड़ रही है लेकिन इससे उन्हें (भाजपा को) कोई फायदा नहीं होगा। महाराष्ट्र में हम 2024 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा, यह चौंकाने वाली बात है कि पीएम मोदी ने कहा था कि एनसीपी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अब उन नेताओं ने राजभवन में शपथ ले ली है।

बिहार में भी होगा महाराष्ट्र वाला खेला!

पटना। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस समय संकट में पड़ गई जब पार्टी नेता अजित पवार ने शरद पवार से अलग होकर राज्य के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। अटकलें लग रही हैं कि क्या जनता दल यूनाइटेड में सब ठीक हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एनडीए में लौटने फिर से बन सकती है? पिछले तीन-चार दिनों की घटनाओं का विश्लेषण करें तो कई राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जो संकेत दे रही हैं कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक संकट हो सकता है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में वापसी कर सकते हैं। नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के विधायकों के साथ आमने-सामने की बैठक ने भी सबका ध्यान खींचा है और उनके अगले कदम पर सस्पेंस बरकरार रखा है। दावा किया जा रहा है कि जदयू के सांसद और विधायक नीतीश के महागठबंधन में जाने से नाराज हैं।

शरद पवार ने एनसीपी की टूट पर कहा-

कुछ लोग भाजपा की रणनीति का शिकार हो गये

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि आज देश और महाराष्ट्र में कुछ समूहों द्वारा जाति और धर्म के नाम पर समाज के बीच दरार पैदा की जा रही है। हम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं लेकिन कुछ लोगों ने हमारी सरकार गिरा दी। देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी ऐसा ही हुआ।

शरद पवार ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि साम्प्रदायिक विभाजन पैदा कर रही ताकतों से लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग दूसरे दलों को तोड़ने की भाजपा की रणनीति का शिकार हो गये हैं। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति पर एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा है कि कराड़ में शरद पवार ने अपने गुरू यशवंतराव चौहान के समाधि पर आकर उन्होंने उनका आशीर्वाद लेकर पार्टी बढ़ाने का शुरूआत करेंगे।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार सोमवार को कराड में अपने गुरु एवं महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवन्तराव चव्हाण के स्मारक पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। वह सोमवार को सुबह पुणे से कराड के लिए रवाना हुए तो रास्ते में कई समर्थकों ने उनका स्वागत किया। कराड में शरद पवार का हजारों समर्थकों और स्थानीय विधायक बालासाहेब पाटिल ने स्वागत किया। कराड से नाता रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण भी उनके साथ नजर आये।

एनसीपी ने की अजीत पवार समेत आठ अन्य विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के समक्ष एक याचिका दायर कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजित पवार और मंत्री पद की शपथ लेने वाले पार्टी के अन्य विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार, जितेंद्र आव्हाड ने रविवार देर रात नार्वेकर के आवास पर याचिका भेजी। अजित पवार के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने के बाद राकांपा ने आव्हाड को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है।

नार्वेकर के कार्यालय से संपर्क करने पर उसने याचिका मिलने की पुष्टि की। राकांपा की अनुशासनात्मक समिति ने भी नौ विधायकों को अयोग्य घोषित करने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया है। समिति के प्रमुख जयप्रकाश दांडेगावकर ने प्रस्ताव पारित होने के बाद रविवार देर शाम राकांपा अध्यक्ष शरद पवार को एक रिपोर्ट सौंपी। प्रस्ताव में कहा गया है, ''नौ विधायकों का यह कृत्य उन्हें तत्काल अयोग्य ठहराने के काबिल है क्योंकि ऐसे दलबदल न केवल पार्टी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि अगर उन्हें विधानसभा सदस्य बने रहने दिया जाता है तो इसकी बहुत ज्यादा आशंका है कि वे पार्टी के हितों को कमजोर करने की कोशिश करते रहेंगे।''

पटेल और तटकरे को शरद पवार ने पार्टी से निकाला

महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल के पीछे शरद पवार ने बड़ा एक्शन लिया है। शरद पवार ने पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनके नाम रजिस्टर से हटवा दिए हैं। शरद पवार का यह एक्शन ऐसे समय में आया है जब उनकी पार्टी में उथल-पुथल मची है। शरद पवार एनसीपी के प्रमुख हैं। उन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। हालांकि, वर्तमान में देखे तो उनके भतीजे अजित पवार उनसे बगावत कर ली है। अजित पवार ने शरद पवार के खिलाफ जाकर शिंदे-भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ कई और नेता शामिल हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल का नाम एनसीपी पार्टी के सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के नाम एनसीपी पार्टी के सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश देता हूं। शरद पवार ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ नेताओं की हरकतों की परवाह किये बिना राकांपा को मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं के विश्वास को बढ़ाने के लिए राज्यव्यापी यात्रा शुरू की है।

जयंत पाटील की जगह तटकरे होंगे एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष

एक ओर जहां एनसीपी में बगावत के बाद शरद पवार एक्शन ले रहे हैं। तो वही अजित पवार गुट ने भी नई शुरुआत कर दी है। अजित पवार गुट में शामिल प्रफुल्ल पटेल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर कहा कि हम शिंदे और भाजपा सरकार के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एनसीपी अजित पवार के नेतृत्व में नई शुरुआत करेगी। अजित पवार एनसीपी विधायक दल के नेता है। उन्होंने संगठन में भी बड़े स्तर पर बदलाव का ऐलान किया। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मैंने महाराष्ट्र(प्रदेश अध्यक्ष) की ज़िम्मेदारी सुनील तटकरे को देने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुनील तटकरे ही संगठन से जुड़े हुए सभी निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि सुनील तटकरे को पार्टी में संगठनात्मक बदलाव करने का अधिकार होगा। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील है। उन्हें हटा दिया गया है। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा कि अनिल भाईदास पाटिल को महाराष्ट्र विधानसभा में राकांपा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया। प्रफुल्ल पटेल ने बोला कि आगे भी संगठन में बदलाव होते रहेंगे। इसके साथ ही विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर उन्होंने कहा कि यह विधानसभा स्पीकर को तय करना है। सुनील तटकरे ने कहा कि मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है।

शिंदे को लेकर जारी अटकलों को भाजपा ने किया खारिज

मुंबई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अजित पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो जाने के बाद वह शिवसेना नेता व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को किनारे लगा सकती है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि शिंदे लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में दावा किया है कि भाजपा महाराष्ट्र में (48 में से) 45 से अधिक लोकसभा सीटें जीतना चाहती है और उसे लगता है कि शिंदे इस दिशा में कुछ नहीं कर सकते।

मुखपत्र में कहा गया, ''शिंदे को (पिछले साल जून में मुख्यमंत्री के रूप में) लाते समय भाजपा ने मराठा कार्ड खेला था। अब उनके पास अजित पवार के रूप में बेहतर मराठा नेता है।'' वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश अकोलकर ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि राज्य के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम से लगता है कि शिंदे को दरकिनार किया जा रहा है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दोनों ही मौजूदा मुख्यमंत्री की तुलना में मुखर, आक्रामक और बेहतर प्रशासक हैं। हालांकि, भाजपा के वरिष्ठ नेता माधव भंडारी ने कहा कि ये सारी बातें 'हवाबाजी' के अलावा और कुछ नहीं हैं। उन्होंने कहा, ''सबसे पहली बात तो यह है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित अयोग्यता याचिका हमारे खिलाफ नहीं जाएगी।

अगर ऐसा होता भी है तो इसका असर सरकार पर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या है।'' कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री शिंदे सहित शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता पर 11 अगस्त तक निर्णय लेना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, ''अगर विधानसभा अध्यक्ष शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाते हैं तो महा विकास अघाड़ी उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी।

शरद पवार के आगे सब फेल हो जाएंगे : लालू यादव

पटना। महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल-पुथल को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने उनसे बगावत कर ली है। शरद पवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अजित पवार ने शिंदे-भाजपा सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके बाद से लगातार बयानों का दौर जारी है। इन सबके बीच राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, उससे शरद पवार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वह मजबूत होकर वापसी करेंगे।

लालू प्रसाद यादव ने कहा कि शरद पवार पर को असर नहीं पड़ने वाला है। शरद पवार एक हैसियत हैं, एक ताकत हैं। उन्होंने कहा कि उस ताकत को नरेंद्र मोदी ने हिलाने की कोशिश की, सब फेल हो जाएंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में ह्यूस्टनपर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया था और अब हमने यह नाटक देखा। यह स्पष्ट रूप से ईडी और उनकी एजेंसियों का प्रायोजित खेल है। इसका महाविकास अघाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम भाजपा के खिलाफ और मजबूती से लड़ेंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

90 मीटर की बाधा पर करने का कोई दबाव नहीं: नीरज चोपड़ा

नयी दिल्ली। पिछले सप्ताह लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले ओलंपिक भालाफेंक चैम्पियन नीरज चोपड़ा ने सोमवार को कहा कि अगस्त में होने वाली विश्व चैम्पियनशिप से पहले शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर फोकस रहेगा लेकिन 90 मीटर की बाधा पार करने का कोई दबाव नहीं है। मांसपेशियों में खिंचाव के कारण तीन शीर्ष स्पर्धाओं में भाग नहीं लेने वाले चोपड़ा ने डायमंड लीग के लुसाने चरण में वापसी करते हुए पिछले सप्ताह 87.66 मीटर की दूरी के साथ लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने पांच मई को दोहा में अपने करियर के चौथे सर्वश्रेष्ठ 88.67 मीटर के थ्रो के साथ सत्र की शुरुआती डायमंड लीग जीती थी।

उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कराई गई वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,'' शारीरिक और मानसिक रूप से दोहा की तुलना में लुसाने में काफी कठिन था क्योंकि बीच में चोटिल होने के कारण पूरा फोकस उस पर रह गया था। सत्र के बीच में चोट लग जाने पर रिकवरी पर फोकस चला जाता है।'' उन्होंने कहा ,'' बीच में मैने तीन कांटिनेंटल गोल्ड स्तर के टूर्नामेंट छोड़े जहां मौसम अच्छा था और मैं 90 मीटर की बाधा पार कर सकता था लेकिन इसका कोई दबाव नहीं है। अभी एशियाई खेल और विश्व चैम्पियनशिप होनी है तो जिस दिन परिस्थितियां बनेंगी, 90 मीटर का थ्रो लग जायेगा। लुसाने के मौसम को देखते हुए प्रदर्शन अच्छा रहा।''

उन्होंने कहा कि अब उनका फोकस 19 से 27 अगस्त तक हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाली विश्व चैम्पियनशिप में सौ प्रतिशत फिट रहकर उतरने पर होगा। चोपड़ा ने कहा ,'' अभी तक मैने विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण नहीं जीता है और इस बार इस कमी को पूरी करने के लिये काफी मेहनत करनी है। फोकस शारीरिक फिटनेस और मानसिक दृढता पर रहेगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

संभावना वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें निर्यातक : वाणिज्य मंत्रालय

नईदिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खाद्य, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग जैसे संभावना वाले प्रमुख क्षेत्रों और 12 प्रमुख बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने की निर्यातकों को सलाह दी है। एक सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करने को भी कहा गया है। मंत्रालय द्वारा उद्योग और निर्यातकों के साथ बैठक के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। अधिकारी ने कहा कि जिन छह क्षेत्रों में देश का निर्यात बढ़ाने की बड़ी संभावना है । उनमें खाद्य, कपड़ा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, फार्मा और वाहन कलपुर्जा शामिल हैं।

अशोक लेलैंड की जून में बिक्री पांच फीसदी बढ़ी

नईदिल्ली। वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली अशोक लेलैंड के वाहनों की बिक्री जून में पांच फीसदी बढ़कर 15,221 इकाई रही। एक साल पहले, इसी महीने में कंपनी ने 14,531 वाहन बेचे थे। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि कुल घरेलू बिक्री आलोच्य महीने में सात फीसदी बढ़कर 14,363 इकाई रही जो एक साल पहले जून महीने में 13,469 इकाई थी। घरेलू मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री पिछले महीने 10 फीसदी बढ़कर 9,274 इकाई रही जो एक साल पहले इसी महीने में 8,399 इकाई थी। हल्के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री जून 2023 मे बढ़कर 5,089 इकाई रही जो एक साल पहले इसी महीने में 5,070 इकाई थी।

विनिर्माण गतिविधियां जून में नरम पड़ीं : पीएमआई

नईदिल्ली। देश में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां पिछले महीने जून में नरम पड़ीं। हालांकि अनुकूल मांग स्थिति के बीच नए ऑर्डर में उल्लेखनीय तेजी के साथ उत्पादन के स्तर पर वृद्धि बरकरार है। मौसमी रूप से समायोजित S&P ग्लोबल इंडिया का विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) घटकर जून महीने में 57.8 रहा जो मई महीने में 58.7 था। इससे पिछले महीने मई में यह 31 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। सर्वे में कहा गया है कि विनिर्माण गतिविधियों में नरमी के बावजूद आंकड़ा परिचालन स्थिति में सुधार को बताता है। मजबूत मांग ने बिक्री, उत्पादन, भंडार निर्माण और रोजगार जैसे अन्य क्षेत्रों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। जून का पीएमआई आंकड़ा लगातार 24वें महीने समग्र परिचालन स्थितियों में सुधार को बताता है। पीएमआई की भाषा में 50 से ऊपर अंक का मतलब विस्तार होता है।

कार्बन क्रेडिट में कारोबार पर एक्सचेंज कर रहे विचार

नईदिल्ली। कुछ बड़े एक्सचेंज कार्बन क्रेडिट में कारोबार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। जब से सरकार ने देश में कार्बन क्रेडिट के विनियमित बाजार की शुरुआती व्यवस्था तय की है तभी से ये एक्सचेंज हरकत में आ गए हैं। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि कृषि जिंसों के सबसे अग्रणी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स ने कार्बन क्रेडिट के वायदा कारोबार के लिए बातचीत शुरू की है। एक्सचेंज इसके वायदा कारोबार के विभिन्न पहलू समझने के लिए अध्ययन भी शुरू कराना चाहता है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) भी स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट बाजार में संभावनाएं ढूंढ रहा है। एनएसई के मुख्य कारोबार विकास अधिकारी श्रीराम कृष्णन ने बताया कि उत्पादों की संख्या बढ़ाने के लिए एक्सचेंज बिजली के डेरिवेटिव्स भी देख रहा है।

अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा से होगा उपभोक्ताओं का लाभ

नारायण कृष्णमूर्ति

अधिकांश भारतीयों का जीवन देश की कुछ बड़ी कंपनियों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही वस्तुओं और सेवाओं पर निर्भर है। आपका मोबाइल कनेक्शन जियो, एयरटेल या आइडिया-वोडाफोन का हो सकता है, आप शायद टाटा का नमक खरीदते होंगे या एअर इंडिया, विस्तारा या एअर एशिया (सभी टाटा समूह से संबद्ध) से यात्रा करते होंगे। आप एयरटेल, टाटा स्काई या जियो नेटवर्क आदि पर टेलीविजन देख रहे होंगे। प्रमुख शेयर बाजार सूचकांकों में इन समूहों से संबंधित कई स्टॉक शामिल हैं-रिलायंस, अदाणी, आदित्य बिड़ला, टाटा या भारती समूह।

इन शीर्ष पांच कंपनियों का विनिर्माण और प्रौद्योगिकी-संचालित क्षेत्रों के अलावा बुनियादी ढांचे से संबंधित कई क्षेत्रों में भी दबदबा है। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य द्वारा लिखे गए एक शोधपत्र के अनुसार, परियोजनाओं के आवंटन में इन्हीं शीर्ष कंपनियों को वरीयता दी गई है, जिसके कारण इन बड़े समूहों द्वारा इंजीनियरिंग, धातु, गैर-धातु खनिज, रसायन, दूरसंचार, खुदरा उत्पाद और पेट्रोलियम जैसे व्यवसायों के नियंत्रण में शक्ति का केंद्रीकरण हो गया है। बिग फाइव कहे जाने वाले इन समूहों की लगभग 40 विभिन्न गैर-वित्तीय क्षेत्रों में व्यापक उपस्थिति है।

इनकी दिलचस्पी प्रमुख बुनियादी ढांचों-बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली वितरण, गैस वितरण, ट्रेन टिकट और यहां तक कि नवीकरणीय ऊर्जा में भी है। हालांकि व्यावसायिक संचालन में शक्ति का केंद्रीकरण कई वर्षों में हुआ है, लेकिन पिछले पांच-सात वर्षों में उनका नियंत्रण तेजी से बढ़ा है। मसलन, वर्ष 2016 में सिविल इंजीनियरिंग

के काम में उनकी हिस्सेदारी 31 फीसदी थी, जो 2021 में 41 फीसदी हो गई। दूरसंचार के क्षेत्र में यह वृद्धि 65 फीसदी से 84 फीसदी हो गई है और परिष्कृत पेट्रोलियम और कोक के निर्माण में यह पहले के 68 फीसदी से बढ़कर 90 फीसदी हो गई है।

यह वृद्धि और नियंत्रण छोटी कंपनियों के अधिग्रहण के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप अनुकूल नियमों के साथ %बिग फाइव% का निर्माण हुआ है, जिससे उन्हें एकाधिकार बनाने में मदद मिली है। दूरसंचार जैसे क्षेत्र में, उपभोक्ता बड़े सेवा प्रदाताओं और उनके द्वारा निर्धारित मूल्यों पर निर्भर हैं, जिसके चलते प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई है। हालांकि कोई इन कंपनियों के पक्ष में नीति निर्माण को लेकर सरकार और इनके बीच किसी तरह की मिलीभगत साबित नहीं कर सकता; लेकिन इससे यह पता चलता है कि कैसे सरकार के नियम %बिग फाइव% को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

विरल आचार्य के मुताबिक, कॉरपोरेट शक्ति के बढ़ते केंद्रीकरण से मुद्रास्फीति के लगातार बने रहने और भारत के बड़े राजकोषीय और चालू खाता घाटे को देखते हुए बाहरी क्षेत्र के मोर्चे पर कमजोरी पैदा होने का खतरा है। ये मुद्दे चिंता का विषय रहे हैं, लेकिन सरकारी चर्चा से बाहर हैं। उदाहरण के लिए, हाल के हफ्तों में विमानों का किराया नई ऊंचाइयों को छू रहा है, कुछ एअरलाइनें जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जबकि कुछ अन्य यात्रियों को भारी किराये के कारण यात्रा से रोक रही हैं। ऐसे ही, जब से संगठित खुदरा व्यवसाय ने स्टोरों और ऑनलाइन बिक्री के जरिये अपने नेटवर्क का विस्तार किया है, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें ऊंची हो गई हैं। आज भारतीय बंदरगाहों पर कुछ चुने हुए व्यावसायिक समूहों का नियंत्रण है; 45 फीसदी सीमेंट उत्पादन, लगभग 30 फीसदी इस्पात उत्पादन और लगभग 50 फीसदी कोयला आयात शीर्ष पांच कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दरअसल, 2014 के बाद से 25 फीसदी नए निवेश प्रस्ताव पांच बड़ी कंपनियों से आए हैं। नहीं भूलना चाहिए कि इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का बड़ी मात्रा में निजीकरण हुआ है और कई पीएसयू निजी ऑपरेटरों के पास चले गए हैं। ये नए उद्यमी नहीं, बल्कि पुराने समूह हैं, जो छोटे और भावी उद्यमों का अधिग्रहण और नियंत्रण करके पूंजी बना रहे हैं।

समान नागरिक संहिता बनने से संविधान निर्माताओं का सम्मान

नीरज कुमार दुबे

समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान के बाद उम्मीद की जा रही है कि देश की बरसों पुरानी मांग जल्द ही पूरी होगी। देखा जाये तो समान नागरिक संहिता यदि हकीकत बनती है तो इससे देश की आकांक्षाएं ही पूरी नहीं होंगी बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं की अपेक्षाएं भी पूरी होंगी। हमारे संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता का पक्ष लेते हुए इसे मूर्त रूप देने का जो दायित्व आने वाली सरकारों पर छोड़ा था, उस संकल्प को यदि मोदी सरकार सिद्ध करती है तो निश्चित ही यह हमारी संविधान सभा के सदस्यों का सम्मान भी होगा। देखा जाये तो संविधान सभा ने जो संवैधानिक प्रावधान किये थे, उन सभी का पालन देश आरम्भकाल से करता आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जिस पर संविधान सभा में सहमति तो थी लेकिन उस पर फैसला करने का दायित्व भविष्य की सरकारों के लिए छोड़ दिया गया था। यह गौर करने योग्य बात है कि उस दायित्व को पूरा करने का साहस पहली बार कोई सरकार दिखा रही है। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग के समक्ष रोजाना ढेरों सुझाव आ रहे हैं। 14 जुलाई सुझाव और विचार भेजने की अंतिम तिथि है, तब तक यह संख्या लाखों में पहुँच सकती है। इसके अलावा, समान नागरिक संहिता को लेकर देश में गली-मोहल्लों से लेकर टीवी चैनलों की डिबेटों और राजनीतिक जनसभाओं के मंचों तक जो चर्चा और बहस का दौर चल रहा है वह दर्शा रहा है कि पूरा देश इस समय इस गंभीर मुद्दे पर मंथन कर रहा है। देखा जाये तो लोकतंत्र में किसी कानून के निर्माण में जितनी ज्यादा भागीदारी होगी वह कानून उतना ही सशक्त होगा। अभी जनता संभावित कानून को लेकर बहस कर रही है। जब मसौदा प्रस्ताव सामने आयेगा तब वह उसके लाभ हानि से जुड़े मुद्दों पर बहस करेगी और जनभावना को ध्यान में रखते हुए संसद में सांसद भी प्रस्तावित विधेयक पर बहस करेंगे। इसलिए जो लोग यह भ्रम फैलाने का अभियान चला रहे हैं कि समान नागरिक संहिता को थोपा जा रहा है उन्हें देखना चाहिए कि जब किसी कानून को बनाने से पहले संपूर्ण प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है तब वह थोपा हुआ कैसे हो सकता है? इसके अलावा, समान नागरिक संहिता के विरोध में तमाम तरह के तर्क दे रहे, समान नागरिक संहिता आने पर तूफान आने की चेतावनी दे रहे और समान नागरिक संहिता आने पर धार्मिक आधार पर विभाजन बढ़ने की बात कह रहे लोगों को देखना चाहिए कि यह देश के लिए नई चीज नहीं है। गोवा में आजादी के बाद से ही समान नागरिक संहिता लागू है। क्या किसी ने सुना है कि वहां पर धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है? क्या किसी ने सुना है कि गोवा में समान नागरिक संहिता की वजह से अल्पसंख्यकों को किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्या किसी ने सुना है कि समान नागरिक संहिता की वजह से किसी को अनावश्यक लाभ या किसी को नुकसान हुआ? जाहिर है इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं में ही होगा। इसलिए जब हमारे समक्ष गोवा जैसा जांचा परखा और खरा उदाहरण है तो समान नागरिक संहिता का विरोध करना सिर्फ %राजनीति% से प्रेरित कदम ही लगता है। देखना होगा कि सरकार संसद के मॉनसून सत्र में ही समान नागरिक संहिता संबंधी विधेयक लाती है या फिर इसे संसद के शीतकालीन सत्र तक टाला जाता है। संसद के शीतकालीन सत्र के समय छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे होंगे, इसलिए यह उस समय भी राजनीतिक दृष्टि से भाजपा के लिए लाभदायक हो सकता है। इस कानून के जल्द ही हकीकत बनने के आसार हैं। बहरहाल, प्रधानमंत्री की ओर से समान नागरिक संहिता की बात कहे जाने के बाद जिस तरह बिना मांगे ही आम आदमी पार्टी और शिवसेना यूबीटी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन कर दिया है उससे विपक्षी एकता को भी धक्का पहुँचा है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक में तय किया गया था कि मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई एकजुट होकर लड़ी जायेगी लेकिन सिर्फ समान नागरिक संहिता आने की सुगबुगाहट पर ही जिस तरह कुछ विपक्षी दलों ने सरकार का समर्थन कर दिया वह दर्शाता है कि यह मुद्दा मोदी सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है।

भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण

प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी,

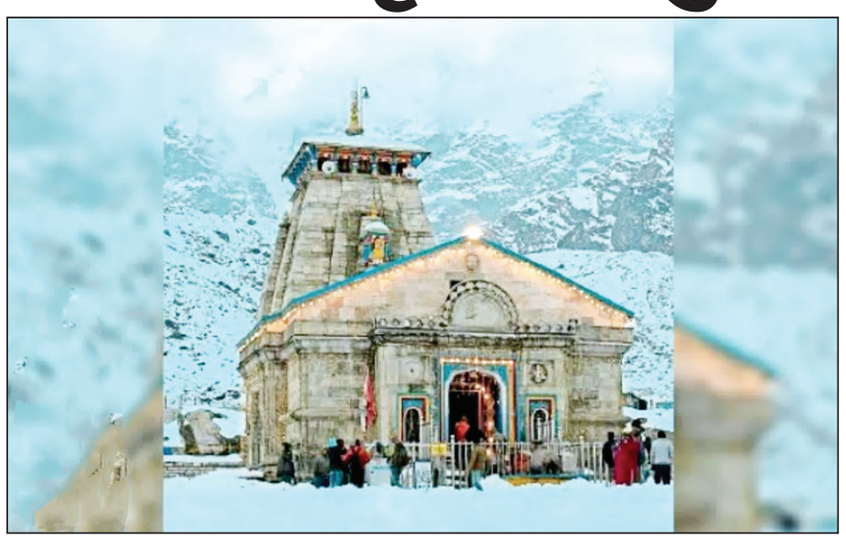

सनातन संस्कृति का यह स्वर्णिम दौर चल रहा है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति के महत्त्वपूर्ण विचारों वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात् पूरा विश्व एक परिवार है तथा सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया: सभी प्रसन्न एवं सुखी रहे, के इन्हीं मूलमंत्रों के साथ सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में हम सभी के मार्गदर्शक बन रहे हैं और समस्त विश्व को सनातन के विचारों से अवगत करवा रहे हैं। एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में हमारा इतिहास करीब साढ़े सात दशक पुराना है, लेकिन हमारी सभ्यता 5,000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत के खाते में अनगिनत उपलब्धियां हैं। उनके स्मरण के लिए इससे बेहतर और क्या अवसर हो सकता है कि जब हम अपनी आजादी के अमृतकाल में हैं, तो केवल इस दिशा में ठोस और एकजुट प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

हम सब इस बात से भलीभाँति परिचित हैं कि भारतीय संस्कृति का विश्वकोष कहा जाने वाला 'रामचरितमानस' दर्शन, आचारशास्त्र, शिक्षा, समाज सुधार, साहित्यिक, आदि कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति को जीवन मूल्यों का दर्शन एवं गुणों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। सदियों से भारत अपनी सांस्कृतिक आध्यात्मिकता के लिए विख्यात है। यह देश आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र रहा है। यहां बहने वाले आस्था के सैलाब को सारी दुनिया देखने आती रही है। अनेक विदेशी यात्रियों ने भी अपने संस्मरणों में इनका उल्लेख किया है। हजारों साल के इतिहास में हमारे श्रद्धा केंद्रों को विधर्मियों द्वारा ध्वस्त किये जाने के बावजूद ये पवित्र स्थल अपने पुण्य प्रवाह के साथ वर्षों से टिके हुए हैं। अपनी उत्कृष्टता का दंभ भरने वाले मिस्र, रोम जैसी सभ्यताओं के चिन्ह आज नहीं के बराबर हैं, उनका एक भी सांस्कृतिक अंश अपने मूल स्वरूप में उपस्थित नहीं है । परन्तु भारत एकमात्र ऐसा देश है, जो यह दावा कर सकता है कि उसने लाखों विपत्तियों के बावजूद अपनी आध्यात्मिकता और आस्था केंद्रों की प्राण शक्ति से अपने सनातन चरित्र को जीवंत रखा है।

यह दैवीय संयोग ही है कि 2014 से भारत के आध्यात्मिक जगत में सांस्कृतिक उत्थान के एक नये युग की शुरुआत हुई। 500 वर्षों से विवादित श्रीराम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और आज मोदी सरकार के नेतृत्व में तेजी से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। भारी प्राकृतिक आपदा झेल चुके हमारे चार धाम में एक केदारनाथ धाम का कायाकल्प भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति से सम्पन्न हो चुका है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा नामक परियोजना परवान चढ़ चुकी है और लगभग सभी दुर्गम आस्था केंद्रों पर अब 12 महीने आसानी से पहुंचा जा सकता है। ऋषिकेश और कर्ण प्रयाग को रेलवे मार्ग से भी जोड़ा जा रहा है, जो 2025 तक पूरा होगा। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के बाद मंदिरों के पुनरुद्धार का काम शुरू हुआ है। श्रीनगर स्थित रघुनाथ मंदिर हो या माता हिंगलाज का मंदिर, सभी प्रमुख मंदिरों के स्वरूप को नवजीवन दिया जा रहा है। पिछले साल भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी का पुनरुद्धार नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से ही संभव हुआ है। आज काशी अपने नए रंगरूप में अपनी आध्यात्मिक पहचान के साथ चमचमा रही है। काशी न्यारी हो गई है। जहां दुनिया भर के लोग आकर वास्तविक भारत और उसकी आध्यात्मिक राजधानी को निहार रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जितना ध्यान देश के मंदिरों के पुनरुद्धार पर दिया है, उतना ही ध्यान विदेशों में भी जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े पुराने मंदिरों की योजनाओं पर भी लगाया है। इस दिशा में सबसे पहले बहरीन स्थित 200 साल पुराने श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए 4.2 मिलियन डॉलर खर्च किये जाने की योजना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा अबूधाबी में भी यहां के पहले मंदिर की 2018 में आधारशिला रखी गई। संयुक्त अरब अमीरात में विशाल हिन्दू मंदिर का लोकार्पण आधिकारिक रूप से वहाँ की सरकार ने किया। जेबेली अली अमीरात के कॉरीडोर ऑफ चॉलरेस में स्थित इस विशाल मंदिर के बनने से वहां के हिन्दुओं का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ है, जिसके पीछे भारत की मोदी सरकार का अथक प्रयास है।

गुजरात के मेहसाणा जिले में चालुक्य शासन में बनाए गये मोढेरा के सूर्य मंदिर का भी पुनरुद्धार हुआ। वहां उड़ी प्रोजेक्शन लाइट एंड साउंड शो के उद्घाटन के दौरान नरेंद्र मोदी जब उसके अतीत का स्मरण करते हुए यह कह रहे थे कि इस स्थान पर अनगिनत आक्रमण किये गये, लेकिन अब मोढेरा अपनी प्राचीन चरित्र को बनाए रखते हुए आधुनिकता के साथ बढ़ रहा है। लगभग एक साल पहले ही सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार और अन्य सुविधाओं के लिए पीएम ने कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। आने वाले समय में सोमनाथ भी आधुनिक सुविधाओं से लैस दिखेगा।

विगत जून महीने में पुणे के देहू में नये तुकाराम महाराज मंदिर और गुजरात के पावागढ़ मंदिर के ऊपर बने कालिका माता मंदिर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया था। पावागढ़ में मां कालिका को नमन करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे श्रद्धास्थल हर भारतीय के प्रेरणा केंद्र हैं और ये स्थल आस्था के साथ-साथ नई संभावनाओं का स्रोत भी बन रहे हैं। काशी, सोमनाथ, केदारनाथ, देहू, पावागढ़ सहित सभी स्थलों पर पुनरुद्धार कार्य के साथ-साथ अनेक जरूरी, विकास और रोजगारपरक योजनाओं को भी अमलीजामा पहनाया जा रहा है। सभी स्थलों पर हजारों करोड़ों की परियोजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है, जो नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। नि:संदेह ऐसे सभी क्षेत्रों में आध्यात्म-संस्कृति का नया सवेरा हुआ है तो विकास की नई गंगा भी प्रवाहित हुई है। सबसे बड़े लोकतीर्थ अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के साथ-साथ लाखों करोड़ की परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर एक्सप्रेस वे तक बन रहा है और अयोध्या को वैश्विक सुविधाओं वाला महानगर बनाने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। काशी, सोमनाथ, केदारनाथ सहित सभी स्थानों पर यही स्थिति है। देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे नई उड़ान मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मोदी देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं, तो वहां के प्रसिद्ध देवालयों में दर्शन-पूजन अवश्य करते हैं। अथवा उनका पुण्य स्मरण करते हैं। हाल ही में नवरात्रि में शक्ति पीठ अंबाजी मंदिर में उन्होंने दर्शन-पूजन करते हुए कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। देश ने विगत 9 सलों में अनेक ऐसे अवसर देखे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान से पहले मोदी जी ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किये तो चुनाव समाप्त होते ही एक दिन के लिए केदारनाथ स्थित गुफा में ध्यान किया।

यह नरेंद्र मोदी की ही प्रेरणा है कि राज्य सरकारों ने भी देवालयों पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश का मथुरा, विन्ध्याचल, प्रयागराज हो या मध्यप्रदेश का उज्जैन हो, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां आधुनिक सुविधाओं से लैस विकास कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा उज्जैन की पावन धरा पर महाकाल लोक के नये कॉरीडोर तथा अन्य लोकमुखी सुविधाओं का उद्घाटन भी इस कड़ी में एक ऐतिहासिक पड़ाव है, जहां से भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पुनरुत्थान का नया अध्याय प्रारंभ होगा। महाकाल की नगरी विश्व भर में विशेष धार्मिक महत्व रखती है, जहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। यही वह धुरी है जिससे भारत में व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन और आर्थिक जीवन के मध्य सदियों से सामंजस्य रहा है। इस दौर का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, तब नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के आध्यात्मिक पुनरुत्थान का योगदान स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा।

हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में ट्ंतमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय'ट्ु की प्रार्थना की है। यानी, हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें। परेशानियों से अमृत की ओर बढ़ें। अमृत और अमरत्व का रास्ता बिना ज्ञान के प्रकाशित नहीं होता। इसलिए, अमृतकाल का ये समय हमारे ज्ञान, शोध और इनोवेशन का समय है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसकी जड़ें प्राचीन परंपराओं और विरासत से जुड़ी होंगी और जिसका विस्तार आधुनिकता के आकाश में अनंत तक होगा। हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को जीवंत रखना है। अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी विविधता को संरक्षित और संवर्धित करना है। और साथ ही, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ की व्यवस्थाओं को निरंतर आधुनिक भी बनाना है।

प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है-मो जीवन पछे नर्के पड़ी थाउ,जगत उद्धार हेउ। अर्थात, अपने जीवन के हित-अहित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ हमारा कर्तव्य है कि हम सभी को पूरी निष्ठा व लगन के साथ काम करना होगा। हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे, तभी वैभवशाली और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

त्रिपुरोपनिषद्

यह उपनिषद् ऋग्वेदीय परम्परा के अन्तर्गत आती है। इसमें सर्वप्रथम चित शक्ति का स्वरूप व्यक्त हुआ है। तत्पश्चात् उस चित् शक्ति की वन्दना की गई है। पुन: कामेश्वर का स्वरूप, आवरण देवता, शिव काम सुन्दरी विद्या का प्रतिफल, आदिमूल विद्या का स्वरूप, विरक्तों (संन्यासियों) की आदिविद्या के ज्ञान का फल, देवी के ज्ञान का फल, मन्द जनों के लिए ध्यान, अधम साधकों के अनुष्ठान और उसके फल तथा निष्काम साधक द्वारा ब्रह्मत्व प्राप्ति का वर्णन किया गया है। यह आगम (तन्त्र) विद्या परक उपनिषद् है। इसलिए इसमें सांकेतिक शब्दों की अधिकता है। ब्रह्म साक्षात्कार का उपाय इस उपनिषद् में बीज मन्त्रों से साधना द्वारा बताया गया है। ऐसी कुछ उपनिषदें हैं, जो जन सामान्य के लिए कुछ कठिनाई से समझ में आने वाली हैं।

तीन पुर, तीन पथ एवं इस (श्री चक्र) में सन्निविष्ट अकथादि अक्षर इन सभी से अधिष्ठित यह (शक्ति) सबको समान दृष्टि से देखने वाली जो अजर, प्राचीन चैतन्य शक्ति है, वह अपनी महिमा से अत्यधिक श्रेष्ठ है। [यहाँ तीन पुर का तात्पर्य स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर से है। तीन पथ का तात्पर्य ज्ञान, कर्म, उपासना- ज्ञान, विज्ञान एवं सम्यक् ज्ञान से है। अकथादि अक्षर से तात्पर्य अ से लेकर क्ष तक अक्षर समूह से है।] (वह चैतन्य शक्ति) नव योनि, नवचक्र, नवयोग, नवयोगिनी, नवचक्रों की आधार शक्तियों, सुखकारी नवभद्राओं तथा महिमाशालिनी नव मुद्राओं के रूप में प्रकाशित हो रही है। [इस मन्त्र के विशिष्ट शब्दों का परिचय इस प्रकार है— नवयोनि श्री चक्र यन्त्र में बनाई जाने वाली नौ योनियाँ (महात्रिपुरसुन्दरी आदि महाशक्तियाँ)। नवचक्र - सर्वानन्दमय सर्वसिद्धिप्रद, सर्वरक्षाकर, सर्वरोगहर, सर्वार्थसाधक, सर्वसौभाग्यदायक, सर्वसंक्षोभण, सर्वाशापरिपूरक एवं त्रैलोक्य मोहन नवचक्रों की आधार शक्तियाँ महात्रिपुरसुन्दरी, त्रिपुराम्बा, त्रिपुरसिद्ध, त्रिपुरमालिनी, त्रिपुराश्री, त्रिपुरवासिनी, त्रिपुरसुन्दरी, त्रिपुरेशी एवं त्रिपुरा। नवयोग- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और सहज योग नवयोगिनियाँ नवचक्रों में निवास करने वाली नौ शक्तियाँ।

क्रमश: ...

स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों से विश्व को सही राह दिखाई

अपनी ओजपूर्ण आवाज से लोगों के दिल को छू लेने वाले स्वामी विवेकानन्द नि:संदेह विश्व गुरु थे जिनके सुलझे हुए विचारों के उजाले ने धर्म की डगर से भटक रही दुनिया को सही राह दिखाई। निर्विवाद रूप से विश्व में हिन्दुत्व के ध्वजवाहक रहे विवेकानन्द का बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्ति से भरा व्यक्तित्व और कृतित्व विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। विवेकानन्द ने अपनी अल्प आयु में ही दुनिया को बहुत कुछ दिया। उन्होंने विश्व को वेदान्त के मर्म से रूबरू कराया। विवेकानन्द ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना। वह चाहते थे कि नौजवान पीढ़ी रूढ़िवाद से अछूती रहकर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल देश की तरक्की के लिए करे। युवाओं के आदर्श विवेकानन्द के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विवेकानन्द के जीवन में विचारों की

क्रांति भरने वाले उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था कि विवेकानन्द एक दिन दुनिया को शिक्षा देंगे और बहुत जल्द अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों से विश्व पर गहरी छाप छोड़ेंगे।

कलकत्ता के शिमला पल्ली में 12 जनवरी 1863 में एक सम्भ्रान्त परिवार में जन्मे विवेकानन्द का बचपन का नाम नरेन्द्रनाथ था। अध्यात्म के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही था और छात्र जीवन में उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी देशों की धर्म तथा दर्शन से जुड़ी पद्धतियों का गहराई से अध्ययन किया। विवेकानन्द ने नए परिप्रेक्ष्य में धार्मिक विचारों के व्यापक प्रचार के लिए वर्ष 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यह शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यों के जरिए सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की शुरुआत थी। रामकृष्ण मिशन आदर्श कर्मयोग पर आधारित है। दिल्ली स्थित रामकृष्ण आश्रम के प्रमुख स्वामी शांतमानंद ने बताया कि विवेकानंद चाहते थे कि देश के युवा रूढ़िवाद से प्रभावित हुए बगैर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को श्रद्धा के साथ निभाएं। उन्होंने कहा कि महज 39 वर्षों की जिंदगी में विवेकानंद ने आधुनिकता की दौड़ में धर्म की राह से भटक रही दुनिया को अपने विचारों की ऊर्जा से सही रास्ता दिखाया। विवेकानंद ने साबित किया कि देश के युवा चाहें तो दुनिया में सुविचारों की क्रांति लाकर अपनी पीढ़ियों को एक सम्पन्न विरासत दे सकते हैं।

लेख में वर्णित तथ्यों के मुताबिक विवेकानंद जिस समय शिकागो गए थे उस वक्त अमेरिका गृहयुद्ध जैसी स्थिति से जूझ रहा था और तथाकथित वैज्ञानिक प्रगति ने धार्मिक मान्यताओं की जड़ों को हिला दिया था। ऐसे में अमेरिकी लोग एक ऐसे दर्शन की प्रतीक्षा में थे जो उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाए। विवेकानंद ने अपने विचारों से उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए आशा की किरण दिखाई। विवेकानंद ने अपने जीवन के आखिरी दिन बेलूरू स्थित रामकृष्ण मठ में बिताए। लगातार यात्राओं से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह शारीरिक रूप से दिन ब दिन कमजोर होते गए। बताया जाता है कि उन्होंने अपने निर्वाण से पहले यह कह दिया था कि वह 40 वर्ष की उम्र तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई और इस आध्यात्मिक गुरु ने अपने विचारों से विश्व को जाजल्यमान करने के बाद चार जुलाई 1902 को दुनिया को अलविदा कह दिया।

यूसीसी, पीओके का अजेंडा बनाम संयुक्त विपक्ष

अमित त्यागी

लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे पास आता जा रहा है वैसे वैसे भाजपा, कांग्रेस और तीसरे मोर्चे का नया स्वरूप आकार लेता जा रहा है। भाजपा के विरोध में बार बार ऐसी कवायद का प्रयास किया जा रहा है जिसमे कांग्रेस और तीसरे मोर्चे को मिलाकर एक संयुक्त विपक्ष बनाया जाये किन्तु इसमे सफलता नहीं मिल रही है। 2024 के लिए एक तरफ सभी विपक्षी दल एकजुट होने का अजेंडा सेट नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं भाजपा 2024 के लिए चुनावी अजेंडा भी सेट कर चुकी है। एक तरफ भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता का विषय ज़ोर शोर से उठाया तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक अधिक्रांत जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के भारतीय भूभाग होने के संसदीय संकल्प का ज़िक्र किया। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता का विषय उठाते हुये स्पष्ट कहा कि हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा। हम तुष्टीकरण के रास्ते पर वोट बैंक के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा रास्ता तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टिकरण है। आज कॉमन सिविल कोड का विरोध हो रहा है जबकि संविधान कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। एक परिवार में रहने वाले दो लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं। ऐसा होने पर परिवार कैसे चलेगा।

हाल ही के दिनो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का

कहना है कि भारत की संसद ने संकल्प लिया है कि पाक अधिक्रांत भूभाग भारत का अभिन्न अंग है। इस संदर्भ में देखा जाये तो भारत की जम्मू, कश्मीर और लद्दाख नीति के संदर्भ में भारतीय संसद द्वारा 22 फरवरी 1994 को पारित प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण एवं आवश्यक दस्तावेज़ है। उस समय की कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री नरसिंह राव के नेतृत्व में भारतीय संसद ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर अपना हक जताते हुए कहा था कि 'यह भारत का अटूट अंग है। पाकिस्तान को वह हिस्सा छोड़ना होगा, जिस पर उसने कब्जा जमा रखा है'। जब तक 370, 35ए नहीं हटी थी तब तक 22 फरवरी को पारित प्रस्ताव भी सिर्फ एक प्रस्ताव दिखाई देता था। इस पर अमल होना एक दुस्वप्न नज़र आता था। किन्तु जब से 370 का खात्मा हुआ है तब से नरसिंह राव द्वारा पारित यह प्रस्ताव भी अपनी पूर्णता की आस दिखाने लगा है। अब जिस तरह से रक्षा मंत्री द्वारा इस विषय को उठाया गया है उसके बाद लग रहा है कि भारत अति शीघ्र इस पर कोई प्रभावी कार्य करने की योजना बना रहा है।

उधर विपक्ष की बात करें तो पटना में सभी विपक्षी दल एक साथ मिले तो वहाँ सबके अपने अपने हित एक दूसरे से टकराते रहे। 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी बौखलाए हुये हैं। वह किसी भी तरफ के भाजपा विरोधी खेमे में शामिल होने को तैयार हैं। तृणमूल कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि अगर कांग्रेस ने वाम दलों के साथ गठबंधन किया तो वह उसके साथ नहीं आयेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह उस गठबंधन में नहीं रहेगी जिसमे कांग्रेस शामिल होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा 2017 का चुनाव एक साथ गठबंधन करके लड़ चुके हैं और इस बार इन दोनों का भी एक साथ आना संदिग्ध है। क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ संयुक्त गठबंधन तो चाहते हैं किन्तु यह भी चाहते हैं कि कांग्रेस कई राज्यों के चुनाव से दूर रहे। कांग्रेस को यह स्वीकार नहीं होगा ? ऐसे में संयुक्त विपक्ष के गठबंधन की कल्पना भी साकार होती नहीं दिख रही है। तीसरे मोर्चे के लिए की जा रही गोलबंदी की ज़िम्मेदारी अब शरद पवार को सौंपी गयी और उनकी ही पार्टी में अजीत पवार के द्वारा बगावत हो गयी।

एक अन्य किरदार नितीश कुमार ने जबसे भाजपा से अपना नाता तोड़ा है तबसे वह भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने को लेकर मुखर रहे हैं। पटना रैली के बाद उनकी मुखरता स्पष्ट रूप से दिख रही है। वह लगातार भाजपा के विरुद्ध एक संयुक्त उम्मीदवार की पैरवी कर रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा पहले हिमाचल प्रदेश और बाद में कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद उसकी राजनीतिक स्थिति सुधरी है। संयुक्त विपक्ष की काल्पनिक अवधारणा में कांग्रेस की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ न आना इस बात का संकेत है कि आप कुछ राज्यों में स्वयं को कांग्रेस का विकल्प मान रही है। विपक्षी एकता की इस कोशिश में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि क्षेत्रीय दल अपने से काफी बड़े एक राष्ट्रिय दल कांग्रेस को सुझाव दे रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए। कांग्रेस के लिए यह अपनी कुर्बानी देने वाली स्थिति है। एक तरफ भाजपा यूसीसी और पीओके के जरिये चुनावी अजेंडा सेट कर चुकी है तो वहीं मोदी विरोधी सभी दल मोदी हटाओं का अभियान तो चला रहे हैं किन्तु बदलाव की इस बयार में न ही कोई वैकल्पिक अजेंडा दे पा रहे हैं और न ही कोई राष्ट्रिय विमर्श खड़ा कर पा रहे हैं। इन सभी दलों में सत्ता में आने से ज़्यादा मोदी विरोध के जरिये मोदी विरोधी खेमे के वोटर को अपने खेमे में लाने की कवायद ज़्यादा चल रही है।

बापू की दिनचर्या

सूत्र-यज्ञ

भारत को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए बापू ने जिन रचनात्मक साधनों का आविष्कार किया, उनमें प्राचीन काल से देश के घर-घर में चलते आए चरखे का पुनरुद्धार मुख्य है। उन्होंने सूत-कताई या चरखे को नई जान दी, नए मंत्र-बल से उसे अभिषिक्त कर, भारतीयों के सामने अपनी दीनता और दरिद्रता को दूर करने के प्रबल साधन के रूप में रखा। यज्ञ किए बिना खानेवाले को वे चोर और पाप का भागी कहते। अत: जब से उन्होंने चरखे का पुनरुद्धार किया, सूत्र-यज्ञ उनकी आवश्यक दिनचर्या हो गई। बापू का यह यज्ञ प्रतिदिन चलता। यह मुक्ति की उनकी साधना थी। दीनता से मुक्ति का साधन इसे वे मानते ही थे, लेकिन मुक्ति की साधना के साथ ही ईश्वर - साक्षात्कार का साधन भी मानते। सूत के धागे धागे में उन्हें ईश्वर दर्शन होता। उनकी मान्यता थी कि जिस साधन से मानव की गरीबी हरी जाती हो, उसमें ईश्वर दर्शन न होता हो, तो वह अपंग साधन है; लेकिन चरखा ऐसा अपंग साधन है नहीं- इसमें दीनता से मुक्ति की शक्ति पूर्ण रूप से भरी है। सूत्र- यज्ञ बापू का व्रत था। एक बार आरंभ की जेलयात्रा में उनको कताई के लिए चरखा सुलभ न हो सका। उस समय उन्होंने भोजन का परित्याग कर सत्याग्रह किया। प्रसिद्ध होने पर ऐसा प्रसंग कभी नहीं आया। सामान्यत: अपराह्न चार बजे बापू का सूत्र-यज्ञ शुरू होता। शरीर के बिलकुल असमर्थ हो जाने तथा रोगशय्या पर पड़ जाने पर ही शायद कताई का उनका क्रम टूट पाता। लंबे-लंबे उपवासों की अवधि में, गोलमेज परिषद् (लंदन) में, जहाँ शयन के लिए भी समय मिलना मुश्किल था, जहाज पर, जेल में और रेल में भी उनका चरखा चलता रहता। किसी कारणवश वे दिन में न कात पाते तो सोने से पहले कातते। भोजन के बिना रहना उन्हें मंजूर था, लेकिन सूत्र- यज्ञ के बिना वे नहीं रह सकते थे।

क्रमश:...

संक्षिप्त समाचार

छग कांग्रेस प्रभारी सचिव सप्तगिरीशंकर 8 को आएंगे छग प्रवास पर

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रभारी सचिव सप्तगिरीशंकर उल्का दिनांक 8 जुलाई 2023 शनिवार को विशाखापटनम कोरबा एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा सुबह 5.23 बजे रायगड़ा से महासमुंद पहुंचेंगे। सुबह 9 बजे वरिष्ठ कांग्रेसजनों से भेट एवं चर्चा। सुबह 11 बजे जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित सरायपाली, बसना, खल्लारी एवं महासमुंद विधानसभा स्तरीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम महासमुंद में करेंगे। 9 जुलाई को सुबह 9 बजे महासमुंद से गरियाबंद के लिये रवाना होंगे। सुबह 10.30 बजे सर्किट हाउस गरियाबंद में वरिष्ठ कांग्रेसजनों से भेट एवं चर्चा। सुबह 11 बजे जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित राजिम एवं बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा स्तरीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओ के साथ बैठक में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम गरियाबंद में करेंगे। 10 जुलाई को सुबह 9 बजे गरियाबंद से धमतरी के लिये रवाना होंगे। सुबह 11 बजे सर्किट हाउस धमतरी में वरिष्ठ कांग्रेसजनों से भेट एवं चर्चा। सुबह 11.30 बजे जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कुरूद, धमतरी एवं सिहावा नगरी विधानसभा स्तरीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे धमतरी से जगदलपुर के लिये रवाना होंगे। रात्रि 9 बजे जगदलपुर पहुचेंगे एवं रात्रि विश्राम जगदलपुर में करेंगे। 11 जुलाई को सुबह 9 बजे सर्किट हाउस जगदलपुर में वरिष्ठ कांग्रेसजनों से भेट एवं चर्चा। सुबह 11 बजे जगदलपुर से कोरापुट (ओडिसा) के लिये रवाना होंगे।

महान प्रेरणा स्त्रोत थे स्वामी विवेकानंद : डॉ चरणदास महंत

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने महान दार्शनिक, संत स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। डॉ महंत ने कहा कि, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने छोटे से जीवनकाल में उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का डंका बजाया, आज भी उनके विचार हमारे जीवन में अनमोल मंत्र के रुप में काम आते हैं। स्वामी विवेकानन्द ने साल 1893 में शिकागो मे सबसे पहले पूरी दुनिया को भारत के धर्म और आध्यात्म के सार से परिचित कराया था। स्वामी विवेकानंद ने केवल वैज्ञानिक सोच तथा तर्क पर बल ही नहीं दिया, बल्कि धर्म को लोगों की सेवा और सामाजिक परिवर्तन से जोडने का कार्य किया।

दंतैल हाथी ने 6 से ज्यादा घरों में की तोड़फोड़, रतजगा करने ग्रामीण मजबूर

जशपुर। कुनकुरी वनपरिक्षेत्र के पुटुकेला और खरवाटोली में शनिवार को दंतैल हाथी ने जमकर उत्पात मचाया. इस दौरान गजराज ने दो गांव के 6 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ की. जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. क्षेत्र में लगातार हाथियों के विचरण के कारण ग्रामीण रतजगा करने को मजबूर हैं।

हाईस्कूल और हायर सेकंडरी के पुनर्मूल्यांकन परीक्षा परिणाम जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं व्याख्याता के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट https://vypam.cgstate.gov.in में अपनी प्रोफाइल में लॉगिन कर परिणाम देख सकते हैं। व्यापम की ओर से लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों में अतिथि शिक्षकों के बोनस अंक जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेंकडरी मुख्य परीक्षा 2023 के पुनर्गणना/ पुनर्मूल्यांकन परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in में परीक्षार्थी अपना रोल नंबर डालकर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। जिन छात्रों ने पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, वे पूरक/अवसर परीक्षा 2023 के लिए आवेदन करना चाहते है, तो जिला मुख्यालय में समन्वय संस्था या विकासखंड के शासकीय स्कूल के माध्यम से 4 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

प्रदेश किसान कांग्रेस के महामंत्री लल्लू सिंह ने थामा आप का दामन

रायपुर। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ते जा रहा है। बीते दिनों बिलासपुर में प्रदेश किसान कांग्रेस महामंत्री लल्लू सिंह ने %आप% का दामन थामा। प्रदेश प्रभारी संजीव झा और प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया। संजीव झा और कोमल हुपेंडी ने लल्लू सिंह को टोपी पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। लल्लू सिंह वर्तमान में प्रदेश किसान कांग्रेस के महामंत्री और रायगढ़ जिला कांग्रेस ग्रामीण के संयुक्त महामंत्री थे। कोमल हुपेंडी ने बताया कि लल्लू सिंह पूर्व में कांग्रेस के कई पदों पर रहे। प्रदेश के अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं का भी आम आदमी पार्टी पर विश्वास और भरोसा बढ़ता जा रहा है। जनता के साथ नेताओं को भी आम आदमी पार्टी में भविष्य दिख रहा है। लोगों को अरविंद केजरीवाल का विकास मॉडल पसंद आ रहा है। हम सभी का स्वागत करते हैं और मिलकर दिल्ली और पंजाब के विकास मॉडल की तरह छत्तीसगढ़ का विकास करना चाहते हैं। दूसरी ओर बीते दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिलासपुर में कहा कि भगवान ने छत्तीसगढ़ को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

मोदी के आने से पहले छत्तीसगढ़ आ सकते हैं अमित शाह

शाह 5 जुलाई को रायपुर आ सकते हैं, लेंगे बड़ी बैठक, 7 जुलाई को रायपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक दलों के सीनियर नेताओं का प्रदेश में दौरा चल रहा है। इसी क्रम में राजधानी रायपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के आने से पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। चर्चा है कि प्रदेश के बीजेपी नेताओं के पास सेंट्रल टीम ने जानकारी भेजी है। जल्द ही शाह के दौरे का प्रोटोकॉल जारी हो सकता है। शाह 5 जुलाई को रायपुर आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, 5 और 6 जुलाई को रायपुर में पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। इसके बाद 6 जुलाई की शाम को वापस चले जाएंगे।

अगर शाह का दौरा कंफर्म होता है, तो पखवाड़ेभर के भीतर वे दूसरी बार प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले वो 22 जून को दुर्ग में एक चुनावी रैली को संबोधित किए थे। इस दौरान पद्मश्री पंडवानी गायिका उषा बारले के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी।

शाह के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आएंगे। इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी नेताओं की अहम बैठक ले सकते हैं। माना जा रहा है कि बैठक में शाह चुनाव तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। हालांकि अभी तक अधिकृततौर पर उनके आने का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द जारी हो सकता है।

इस वजह से हो रहा दौरा

इस साल नवंबर में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश में के सियासी गलियारे में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लगातार मोदी सरकार के केंद्रीय नेताओं समेत अन्य दलों के नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। अमित शाह के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, फिर 2 जुलाई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान बिलासपुर आए थे।

शाह के संभावित दौरे पर लखमा ने कसा तंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले केंद्रीय

गृहमंत्री अमित शाह का दोबारा छत्तीसगढ़ आने की खबर पर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र घटनाक्रम के बाद शाह के हर कदम पर नजर रहेगी। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर शाह की सक्रियता पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसा है। मंत्री लखमा ने अमित शाह के प्रदेश दौरे को लेकर तीखा हमला बोलते हुए कहा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग बली ने अमित शाह को लात मार दिया। अब भगवान भी उनके साथ नहीं है तो जनता कहां से उनके साथ होगी। कवासी लखमा ने उस वक्त यह बयान दिया जब सुकमा के 30 आदिवासी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ये सभी आदिवासी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। इन सभी लोगों ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा के सामने कांग्रेस का दामन थाम लिया। जैसे कि खबर आ रही है, शाह पांच और छह जुलाई को रायपुर में पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक लेने के बाद छह जुलाई की शाम को वापस चले जाएंगे।

आप की सभा से बढ़ी भाजपा की चिंता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए मिला टारगेट

बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड पर आ चुकी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही टूट के बाद प्रदेश में आम आदमी पार्टी सक्रिय हो चुकी है। रविवार को बिलासपुर में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ी सभा की। इस सभा में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचे थे। इस सभा के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि जेपी नड्डा की सभा में जितनी भीड़ जुटी थी उससे कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी की सभा में थी। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सभा में 25 हजार से ज्यादा की भीड़ जुटी थी।

भाजपा के लिए नई मुसीबत

विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी की सभा में जुटी भीड़ ने विरोधियों को बड़ा संदेश दिया है। जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में विकराल भीड़ जुटाने का लक्ष्य बीजेपी नेताओं को मिला है। क्योंकि जेपी नड्डा की सभा में बीजेपी ने दावा किया था कि वो 80 हजार की भीड़ जुटाएगी।लेकिन ऐसा हो ना सका।जेपी नड्डा की सभा में 20 हजार तक ही आंकड़ा पहुंच सका था। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सभा में जुटी भीड़ ने कहीं ना कहीं ये संकेत दिया है कि आने वाले चुनाव में उसे कमतर आंकना गलती होगी।

प्रधानमंत्री आ रहे हैं रायपुर

छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता वापसी की राह देख रही है। जिसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव के कई महीने पहले से ही प्रदेश में घेराबंदी करनी शुरु कर दी है। लेकिन अब तक बीजेपी की जितनी भी सभाएं प्रदेश में हुई हैं। उनमें उतना बड़ा जनसैलाब देखने को नहीं मिला जितना अक्सर देखने को मिलता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सभा में जुटी भीड़ ने पीएम मोदी की सभा के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया है। लिहाजा मोदी की सभा के लिए कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का टारगेट सौंपा गया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा में नहीं जुटी थी भीड़

बिलासपुर में केजरीवाल से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दौरा किया था।लेकिन 15 साल तक राज करने वाली बीजेपी के लिए इस सभा में उसके कार्यकर्ता नजर नहीं आए।जिसके लिए स्थानीय नेताओं को नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी।अब प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है।ऐसे में यदि जेपी नड्डा की सभा जैसा हाल प्रधानमंत्री की सभा में रहा तो ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जाएंगे।

भाजपा में यूज एंड थ्रो होते हैं नेता, हमारे यहां नहीं : भगत

रायपुर। रविवार को छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने प्रेस कांफ्रेंस कर अपने 4 साल के कार्यकाल का लेखाजोखा मीडिया के सामने रखा। अपनी उपलब्धियों के दौरान उन्होंने इस चार साल में फिल्म सिटी निर्माण पूरा ना होने की बात कबूली। उन्होंने बताया कि फिल्म सिटी निर्माण के लिए सही जमीन नहीं मिल पा रही है। भगत ने भाजपा पर भी जमकर हमला बोला।

सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने पर भाजपा के पलटवार पर भगत ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहली बार छत्तीसगढ़ में देखा कि बीच में नेता प्रतिपक्ष ओर प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है कि किसी को हटाया गया हो। सबको सम्मान और स्थान दिया गया है। भगत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में होता है कि काम निकलने के बाद नेताओं

को किनारे कर देते हैं। वहां यूज एंड थ्रो होता है। अटल, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी हो, उनकी पार्टी में ऐसा होता है। हमारे यहां ऐसा नहीं होता।

फिल्म सिटी बनाने के लिए जमीन की तलाश जारी

भगत ने बताया कि फिल्म सिटी निर्माण के लिए जितनी जमीन की जरूरत है, उतनी जमीन अभी सरकार को नहीं मिल पाई है। नया रायपुर में जगह देखी गई है, लेकिन वह काफी नहीं है। महासमुंद में भी जगह की तलाश की जा रही है, लेकिन फिल्म सिटी निर्माण के लिए पहली प्राथमिकता सरकार की नया रायपुर ही है। अमरजीत ने कहा कि एनआरडीए (नया रायपुर विकास प्राधिकरण) यदि सरकार को जमीन उपलब्ध करा देता है, तो इस काम को लेकर आगे बढ़ाया जा सकता है।

लोक कला को प्रोत्साहित कर रही सरकार

संस्कृति विभाग से जुड़े सवालों के जवाब में मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि हमारी सरकार ने गांव-गांव में रामायण कराने की परंपरा शुरु की। पहली बार सांस्कृतिक परिषद का गठन किया गया। जिसके अंतर्गत 7 अकादमी संचालित हैं। लोक कला और लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने चिन्हारी पोर्टल चलाया गया है। इसमें 8 हजार 500 कलाकार पंजीकृत हैं। कलाकारों के भुगतान को लेकर नये नियम बनाए गए हैं। लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।

छत्तीसगढ़ी संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश

छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग द्वारा भारत भवन, मानव संग्रहालय एवं विवेकानंद स्मृति संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कलाकार विदेशों में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली, आईसीसीआर और राज्य शासन के बीच एमओयू हुआ है।

प्रदेश सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल

रायपुर। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ की मांग पूरी नहीं हुई। लिहाजा उन्होंने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संविदा कर्मचारियों की इस हड़ताल में प्रदेश के सभी विभागों के संविदा कर्मचारी है। प्रदेशभर के लगभग 45 हजार कर्मचारियों ने आज से काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। प्रदेशभर के स्वास्थ्य, मनरेगा, पंचायत, कृषि, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल से इन विभागों में काम रुक जाएगा। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ अपनी 1 सूत्रीय मांग नियमितीकरण को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहा है। पिछले महीने महासंघ ने नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन भी किया था। कर्मचारियों ने सरकार पर साल 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा ना करने का आरोप लगाते हुए काम बंद कर हड़ताल करने की चेतावनी दी थी। प्रदर्शनकारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए चुनाव में इसका नतीजा भुगतने की चेतावनी भी दी थी। महासंघ ने बताया था कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया गया लेकिन पिछले साढ़े 4 सालों से कांग्रेस सरकार ने नियमितीकरण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की। जिसके कारण संविदा कर्मचारियों में आक्रोश और नाराजगी है। सरकार को अल्टीमेटम देते हुए विधानसभा चुनाव में संविदा कर्मचारियों और उनके परिवार ने दूसरे पार्टी को वोट देने की चेतावनी भी दी थी।

छत्तीसगढ़ के बारे में क्या जानते हैं केजरीवाल, उनके सारे दावे झूठे: भूपेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान की कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता को फ्री की रेवडियां बांट रही है। बघेल ने कहा कि केजरीवाल को छत्तीसगढ़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो केवल राजनीति करते हैं। पीएम के 7 जुलाई को प्रस्तावित दौरे पर कहा कि छत्तीसगढ़ को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि वापस की जानी चाहिए। साथ ही राजधानी रायपुर में कार्गो एयरपोर्ट की सुविधा मिलनी चाहिए। कोल रायल्टी की बकाया राशि दी जानी चाहिए।

श्री बघेल ने आगे कहा कि केजरीवाल कृषि और आदिवासियों, किसानों पर कुछ नहीं बोल पाए। छत्तीसगढ़ में चार सौ यूनिट तक बिजली

हाफ है, स्वामी आत्मानंद स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल रही है। संकट के समय सरकार की असली पहचान होती है। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय छत्तीसगढ़ से एक भी पलायन नहीं हुआ। सात लाख लोग यहां आए। उनके रहने-खाने का इंतजाम किया गया। जबकि लॉकडाउन की घोषणा के 24 घंटे के भीतर दिल्ली से लाखों लोग यूपी और बिहार निकल गए। केजरीवाल उन्हें राहत पहुंचाने के लिए कुछ नहीं कर सके।

श्री बघेल ने याद दिलाया कि ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी तब छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्यप्रदेश, राजस्थान, विदर्भ, पंजाब, को ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर राहत पहुंचाने की दिशा में काम किया जबकि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। प्रियंका जी का फोन आया तो हमने कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई। मगर केजरीवाल का एक फोन तक नहीं आया। लोग तड़पते रहे, और वो राजनीति करते रहे।उन्होंने कहा कि पंजाब को देश के सबसे कर्जदार सरकार के रूप में ला खड़ा किया है। केजरीवाल के सारे दावे झूठे हैं, जनता उन्हें अच्छी तरह से पहचानती है

उन्होंने कहा कि पीएम 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। इससे पहले श्री बघेल ने केन्द्र से मांग करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि वापस कर दी जाए, साथ ही राजधानी रायपुर में कार्गो एयरपोर्ट की सुविधा मिलनी चाहिए।

धमतरी में बिना मुआवजा दिए बन रही थी सड़क, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

- नगर निगम और महापौर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

बिलासपुर। धमतरी में निजी जमीन का मुआवजा दिए बिना सड़क बनाने की कोशिश करने के मामले में सोमवार को हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग पर स्टे दे दिया है। साथ ही निगम को मामले पर अगले आदेश तक यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है यानी जो सड़क जबरन बनाई जा रही थी, उस पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों और महापौर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने नजूल राजस्व अधिकारी से सीमांकन कराने का भी आदेश जारी किया है। धमतरी नगर निगम क्षेत्र में रहने वाली कुमारी उरमाल मुंजवानी की जमीन सुभाष नगर कांटा तालाब के पास है। नगर निगम धमतरी ने इस पर सड़क बनाने की कवायद शुरू कर दी है।

नगर निगम धमतरी की ओर से निजी जमीन पर अवैध और गैरकानूनी रूप से कब्जा कर ट्रैक्टर व जेसीबी का इस्तेमाल करते हुए सड़क निर्माण करना

शुरू कर दिया है। इस मामले की जानकारी लगते ही उरमाल मुंजवानी ने निगम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन निगम नहीं माना। इस पर उरमाल मुंजवानी ने एडवोकेट आरएस पटेल के माध्यम से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई और स्टे आर्डर दिया गया। कोर्ट ने सीमांकन करने का भी दिया निर्देश- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूरे मामले में अपना अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने जारी आदेश में कहा है कि आवेदन करने वाले की निजी जमीन पर नगर निगम द्वारा यथास्थिति बनाया जाय। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला करते हुए सीमांकन कराने का भी आदेश दिया है। सीमांकन नजूल एवं राजस्व अधिकारी की ओर से किया जाएगा। सीमांकन के समय नगर निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। साथ ही कोर्ट ने निगम के अधिकारियों और महापौर को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए निर्देशित किया है।

विकास के नए रास्ते खोलेंगी छत्तीसगढ़ की सड़कें: मुख्यमंत्री बघेल

बीते साढ़े चार वर्षों में सड़कें एवं पुलों के 7 हजार 406 कार्यों के लिए 16 हजार 670 करोड़ रूपए की स्वीकृति

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में विश्वास और विकास का जो रोडमैप तैयार किया है, वह अब आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ की सड़कें यहां की लाइफ लाइन हैं जो आने वाले समय में विकास के नए रास्तें खोलेंगी, व्यापार बढ़ेगा , पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों के विकसित होने के साथ आर्थिक तौर पर छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाके समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। यह सब कुछ संभव होगा सड़कों के उन कारिडोर से जिसे बढ़ाने का काम जारी है।

राज्य में बीते साढ़े चार साल में राज्य में विभिन्न योजनाओं में सड़क एवं पुल के 7406 कार्यों हेतु लगभग

16 हजार 670 करोड़ रूपए तथा इस दौरान भवनों के 419 कार्यों हेतु लगभग 908 करोड़ रूपए की स्वीकृति मिल चुकी है । विगत 4 वर्षों में राज्य मद के अंतर्गत 9884 कि.मी. सड़कों का उन्नयन किया जा चुका है। इनमें 4 हजार 41 कि.मी. सड़कों का नया डामरीकरण , 3 हजार 244 कि.मी. सड़कों का डामरीकृत नवीनीकरण, 1 हजार 113 कि.मी. सड़कों का चौडीकरण, 588 कि.मी. सड़कों का मजबूतीकरण तथा 898 कि.मी. सड़कों का सीमेंट कांक्रीटीकरण किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के अनुसार विश्वास, विकास एवं सुरक्षा ही सरकार का मूलमंत्र है। मुख्यमंत्री के अनुसार छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना सबसे जरूरी है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीणों तक राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार माध्यम, रोजमर्रा की चीजें, रोजगार व आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है, जिसके लिए सड़क एक महत्वपूर्ण साधन है।

बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर जैसे जिलों के दुर्गम इलाके धीरे धीरे मुख्य धारा में शामिल होते जा रहे हैं। सड़कों के निर्माण और मरम्मत से किसानों की पंजीयन संख्या बढ़ी है, इन क्षेत्रों में धान की बिक्री बढ़ी है, वनोपज संग्रहण एवं विक्रय कार्यों में तेजी आई है और छत्तीसगढ़ में रोजगार के साधन भी उपलब्ध हुए हैं।

महाराष्ट्र में सरकार नहीं तीन चक्के वाली ऑटो रिक्शा हो गई है : भूपेश

रायपुर। महाराष्ट्र के सियासत में अचानक एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो गया। जिससे हर कोई हैरान रह गया। एनसीपी नेता अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) से अजित पवार ने बगावत करने के बाद शिंदे सरकार में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस इस पर तंज कसा है।

बघेल ने कहा कि महाराष्ट्र में पहले शिवसेना को तोड़ा गया और अब एनसीपी को। पहले डबल इंजन की सरकार थी अब ट्रिपल इंजन हो गई। यह सरकार नहीं ऑटो रिक्शा हो गई है, तीन चक्के वाली। मैंने देखा की शपथ ग्रहण में फडणवीस और पवार दोनों एक तरफ बैठे मुस्कुरा रहे हैं और दूसरी तरफ शिंदे बैठे हैं जिनका चेहरा उतरा हुआ है। यह घटना आने वाले समय में होने वाले घटनाक्रम का संकेत दे रही है। शरद पवार ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं।

पीएम मोदी का आगमन हमारा सौभाग्य : मूणत

- पीएम मोदी की सभा को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर
- मूणत ने किया रायपुर पश्चिम विधानसभा के चारो मंडलों का दौरा, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक
- मूणत ने ली रायपुर पश्चिम विधानसभा के चारो मंडल की महत्त्वपूर्ण बैठक

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की आम सभा मे कार्यकर्ताओं की भीड़ सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी आगामी 7 जुलाई को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आमसभा को सम्बोधित करने वाले हैं।

भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने सोमवार को अपने आवास में कार्यक्रम की तैयारियों के सम्बंध रायपुर पश्चिम विधानसभा के चारो मंडल का दौरा करके कार्यकर्ताओं की महत्त्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समय कम बचा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन से कार्यकर्ताओ में जबरदस्त उत्साह है।

उन्होंने कहा कि रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मोदी जी का आगमन हमारा सौभाग्य है। मैंने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में मंत्री और विधायक रहने के दौरान रायपुर पश्चिम विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं की सतत बैठके लेता रहा हूँ। आज की बैठक के बाद मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की आमसभा होने से क्षेत्र का एक-एक कार्यकर्ता उत्साहित है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बनाने के लिए रायपुर पश्चिम विधानसभा के 10 हज़ार कार्यकर्ताओ को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है,इसके लिए वार्ड पार्षदों के अलावा छाया पार्षदों और मंडल से लेकर बूथ स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तरह तैयारी है। हमारा अनुमान है कि कार्यक्रम स्थल पर एक से डेढ़ लाख लोगों कार्यकर्ताओ की भीड़ जुटेगी । जबकि रायपुर जिले से ही 50,000 से ज्यादा भीड़ जुट सकती है।

मूणत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए विशाल पंडाल पूरी तरह से वॉटरप्रूफ तैयार किया जा रहा है। मंडल स्तर पर लगातार बैठकें लेकर तैयारियां की जा रही हैं।

मेरी बात

✍ गिरीश पंकज

जहरीले लोग!

जहर केवल साँपों में नहीं होता। कुछ मनुष्यों के भीतर भी भरा होता है। मगर वे समझ नहीं पाते कि यह ज़हर है। पहले लोग अपनी कुंठा कहीं उगल नहीं पाते थे। लेकिन उनकी निराशा, हताशा, कुंठा को उगलने का एक माध्यम उपलब्ध हो गया है, जिसे वे फेसबुक कहते हैं। या सोशल मीडिया। कुछ के लिए फेसबुक मानवता को आगे बढ़ाने का माध्यम है। कोई धर्म, जाति, संप्रदाय कैसे मिलजुल कर रहे, इस की कोशिश में रचनात्मक टिप्पणियां करते रहते हैं, महापुरुषों के वचन भी कुछ लोग पोस्ट करते हैं। अनेक बन्धुओं की बातें सकारात्मक बोध से भरी होती हैं। लेकिन कुछ लोगों को

टिप्पणियां हमेशा नकारात्मक नजर आती है। मैं समझ पाता कि उनमें इतनी नकारात्मक कैसे आ गई? क्या इसलिए कि जिस कार्यालय में वे काम कर रहे हैं, वहाँ काम का दबाव अधिक है, या उनका अधिकारी उनको हर वक्त फटकारता रहता है? या पत्नी से झगड़ा होता रहता है। जो भी, मगर जैसे ही वे फेसबुक खोलते हैं, दिन भर की सारी कुंठाएं यही उतार देते हैं। उनकी बातों से लगता है कि वे विश्व के महानतम क्रांतिकारी हैं। जबकि उनका जीवन हम देखते हैं, तो पता चलता है कि वे किसी बड़े भ्रांतिकारी से कम नहीं। बेहद डरपोक,कायर, बॉस के आगे दुम हिलाने वाले।

अगर आप कोई भली बात भी कह दी तोये क्रांति बनाम भ्रान्तिकारी आपका समर्थन नहीं करेंगे, उल्टे कुछ ऐसा कहेंगे, गोया आपने बहुत ही गंदी बात कह दी । मान लो आपने लिख दिया कि गौ मांस नहीं खाना चाहिए, गौ हत्या बुरी बात है। मांसाहार स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, बस देखिए, आपकी कैसी फजीहत करेंगे। कुछ अच्छी टिप्पणियों से आपके विचार स्वागत होगा कि आपने बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन कुछ खास पंथ के पथिक आप पर पिल पड़ेंगे। बहुत चलताऊ जुमला पेश करेंगे कि कोई क्या खाए, क्या पहने, इससे आपको क्या लेना देना। कोई कहेगा आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। मैं समझ नहीं पाता कि मांसाहार से रोकने की बात करना कहा की सांप्रदायिकता है ।गाय तो विश्व की माता कही जाती है ।उसकी हत्या का विरोध करना कैसे हो गई सांप्रदायिकता? क्या गाय को काटना किसी संप्रदाय विशेष का धार्मिक अनुष्ठान है? अगर यह धार्मिक अनुष्ठान है, तो ऐसे धर्म के बारे में हमें सोचना चाहिए,जो हिंसा की वकालत करता है। मैं समझता हूं दुनिया का कोई भी धर्म कभी भी हिंसा की बात नहीं करेगा। वह हर मनुष्य के भीतर करुणा, सद्भाव, प्रेम, भाईचारे की भावना जगाने की ही बात करेगा। अगर किसी धर्म में अलगाववाद है, वह हिंसा के लिए प्रेरित करता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। कभी आपने भूल से भी प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी कि देखिए उनके कारण दुनिया में भारत का कितना नाम रोशन हो रहा है, कोई राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर छू रहा है, कोई उनको बॉस कह रहा है तो लगी मिर्ची। पड़ने लगी गाली। जो दूसरी विचारधारा के हैं, चिढ़ जाएंगे और बोलेंगे, प्रधानमंत्री ने अँग्रेज़ी के एक शब्द का गलत उच्चारण किया था, या भीड़ प्रायोजित थी। ये दो उदाहरण दिए हैं। कुण्ठा ग्रस्त आदमी केवल गाली देगा। विरोध करते हुए बड़ी गंदी और कड़वी बातें कहेगा। लिखने में संकोच नहीं करेगा। ऐसे नकारात्मक बोध वाले बढ़ते जा रहे हैं। तब मुझे कहना पड़ता है ,

बात मोहब्बत की कुछ करते,
कुछ बस घृणा बढ़ाते हैं।
जिसके जीवन में जो है,
वो लोगों तक पहुँचाते हैं।

नितिन और अरुण ने ली संयुक्त बैठक, विस चुनाव पर की चर्चा

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के छत्तीसगढ़ प्रवास की तैयारियों की दृष्टि से प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों की संयुक्त बैठक सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा के साथ ही पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। बैठक में बैठक में प्रदेश भाजपा सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि हमारा कार्यक्रम ऐसा हो कि अपने कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का विश्वासपूर्ण संदेश लेकर जाएँ। सभी मोर्चा पदाधिकारियों को सौंपे गए कार्यों की समीक्षा की और शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में वैचारिक रूप से जुड़े लोगों को अधिकाधिक संख्या में प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यक्रम में लाने की चर्चा हुई। मोर्चावार संख्या को लेकर भी बैठक में विमर्श हुआ। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी श्री नबीन ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यक्रम में संख्या की मॉनीटरिंग के लिए अलग-अलग टीम बनाने के लिए निर्देशित किया। श्री नबीन ने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि वे सोशल मीडिया का सदुपयोग करें और भाजपा की विचारधारा से युवाओं को जोड़ने कॉलेज, कोचिंग सेंटर और खेल मैदानों तक पहुँचें ।बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जनता से सीधा संवाद करता चाहते हैं। अत- उनके कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में सबकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए ।संयुक्त मोर्चा की बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत, महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी राजपूत, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष शकील अहमद, एसटी मोर्चा अध्यक्ष विकास मरकाम, किसान मोर्चा अध्यक्ष पवन साहू, एससी मोर्चा अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय, किशोर महानंद, रामू अरोरा सहित रायपुर संभाग के सभी मोर्चा के जिला अध्यक्ष महामंत्री व प्रभारी गण उपस्थित थे।

साव ने स्वामी शिवरूपानंद से लिया आशीर्वाद

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सोमवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजधानी के वीआईपी रोड स्थित भारत सेवा आश्रम पहुँचे। आश्रम में पहुँचकर श्री साव ने संत-दर्शन के निमित्त स्वामी शिवरूपानंद पांडेय के दर्शन किए और छत्तीसगढ़ प्रदेश की सुख-शांति, समृद्धि, परस्पर सद्भाव, सामाजिक समरसता की अक्षुण्णता के लिए आशीर्वाद लिया।

इस अवसर पर स्वामी शिवरूपानंद जी के साथ श्री साव ने आश्रम परिसर में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का अवलोकन किया और भारत माता की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा निवेदित की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि भारत सेवा आश्रम ने सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी चेतना को जीवंत रखा है तथा धर्म व अध्यात्म के पवित्र सूत्र से समाज-जीवन को संस्कारबद्ध किया है। श्री साव ने कहा कि संत-समाज ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम को लक्ष्यकेंद्रित दिशा प्रदान कर भारतीय समाज-जीवन में अलख जगाने के लिए महती भूमिका निभाई है।

राज्यपाल हरिचंदन ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के दिए निर्देश

रायपुर। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अधिकारियों को राजभवन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं. राजभवन में उपयोग होने वाली किसी भी सामग्री के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े के थैले या जूट के थैले इस्तेमाल किए जाएं.उन्होंने कहा कि, आज विश्व के सामने प्लास्टिक से हो रहा प्रदूषण सबसे बड़ी चुनौती है. हम सबको सक्रिय रूप से इस इसका उपयोग कम करने और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए हम सबको अपना माइंड सेट बदलना होगा और जब भी बाजार जाएं तो अपने साथ कपड़े का या जूट का थैला अवश्य ले जाएं. प्रकृति हम सबका संरक्षण करती है. राज्यपाल ने प्रदेश वासियों सहित देशवासियों से अपील की है कि, आज से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का प्रण लें और इस धरती को और बेहतर बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करें. राज्यपाल हरिचंदन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि, राजभवन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए. राजभवन में उपयोग होने वाली किसी भी सामग्री के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े के थैले या जूट के थैले इस्तेमाल किए जाएं।

जनचौपाल में कलेक्टर ने सुनी समस्या

रायपुर। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित सभाकक्ष में आयोजित जनचौपाल में जामजनों की समस्याएं सुनी। जनचौपाल में 72 आवेदन आए जिसपर कलेक्टर ने अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री बी.बी पंचभाई, एसडीएम श्री देवेन्द्र पटेल उपस्थित थे।जनचौपाल में संतोषी नगर निवासी सुश्री रीतु टंडन ने गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते हुए बताया कि रायपुर जिले में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक (अनु.जनजाति) के लिए आयोजित साक्षात्कार में वह शामिल हुई थी।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

महंगाई बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था मोदी सरकार की उपलब्धिः मरकाम

रायपुर । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बढ़ती महंगाई बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था मोदी सरकार की उपलब्धि है और भाजपा के नेता इस उपलब्धि के यशोगान करने के लिए गांव गांव और गली गली घूम रहे हैं। और मंहगाई से जख्मी जनता के जख्मों पर नमक छिड़क कर जला रहे हैं भाजपा नेताओं में थोड़ी बहुत भी नैतिकता बाकी होगी तो उन्हें प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि मोदी सरकार ने जो 100 दिनों महंगाई कम करने अच्छे दिन आने 15-15लाख रुपए खाते में जमा कराने 30 से 35 लीटर पेट्रोल डीजल देने सस्ते दरों में रसोई गैस देने सस्ते दरों में खाद्यान्न उपलब्ध कराने का जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाए हैं आज देश की जनता महंगाई बेरोजगारी से पीड़ित है और भाजपा के नेता जश्न मना रहे और महंगाई से पीड़ित जनता के जख्मों पर नमक छिड़क रहे है। मनमोहन सरकार के दौरान पेट्रोल डीजल के दाम में 25 पैसा की बढ़ोतरी होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता छाती पीटते थे सड़कों पर उतर कर हाय तौबा मचाते थे, आलू प्याज की माला पहनते थे, रसोई गैस का सिलेंडर लेकर धरना देते थे। आज देश की जनता जब महंगाई से त्रस्त है तो भाजपा के नेताओं के मुंह में फेवीकोल जम गया है जिनके हाथों में महंगाई कम करने की ताकत जनता ने दिया है>

किसानों के नाम पर सियासी ड्रामेबाजी कर रही : कौशिक

रायपुर। पुर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश के किसानों की स्थिति को देखते हुए उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि टीएस बाबा प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बन चुके है इसके बाद भी अंबिकापुर की स्थिति लगातर बिगड़ रही है खाद को लेकर के किसानों के बीच में लगातार चर्चा हो रही है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने में प्रदेश सरकार पुरी तरह से असफल है साथ ही खाद के नाम पर जिस प्रकार किसानों मट्टी परोसा जा रहा है उससे किसानों में और अधिक आक्रोश दिख रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती अनिश्चित काल के लिये लगतार घंटों-घंटों तक की जा रही है, जिसे लेकर अंबिकापुर के कार्यकर्ता एवं वहां की जनता बिजली ऑफिस का लगातार घेराव कर रहे हैं एवं आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी वहां की स्थिति सुधरने के बजाय हालात बेकाबु हैं। इस बात को लेकर के किसानों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की आवश्यकता और अधिक होती है ऐसे समय में कांग्रेस किसानों को लगातार धोखा दे रही है जिससे किसान हालाकान है। टीएस सिंहदेव के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद स्थिति सुधरनी थी इसके विपरित स्थिति बदहाल होते जा रही है। किसानों को भ्रम में रखना कांग्रेस की पहली प्राथमिकता हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर सियासी ड्रामेबाजी कर रही है प्रदेश की कांग्रेस सरकार को किसानों की हित की कोई फिक्र नहीं है।

छत्तीसगढ़ को क्यों भूल गये थे पीएम मोदीः शुक्ला

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मजबूती और कांग्रेस सरकार के कामो से भाजपा का केन्द्रीय नेतृत्व डरा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा का नेतृत्व को इस बात का अहसास हो गया है कि स्थानीय नेतृत्व के भरोसे छत्तीसगढ़ में भाजपा दहाई अंको तक भी नहीं पहुंच पायेगी। इसीलिये भाजपा के राष्ट्रीय नेता घबराहट में छत्तीसगढ़ की ओर दौड़ लगा रहे है। लेकिन इनके पास राज्य की जनता के लिये राज्य की जनता की भलाई के लिये कोई कार्ययोजना नहीं है वे सिर्फ राज्य की जनता को ठगने की नीयत से छत्तीसगढ़ आ रहे है। प्रधानमंत्री मोदी को छत्तीसगढ़ की याद 4 साल तक नहीं आई। छत्तीसगढ़ की जनता ने 9 सांसद जिताकर भेजा था लेकिन भाजपा की केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के प्रति सौतेला रवैय्या रखा। चुनाव सामने देखकर भाजपा को छत्तीसगढ़ की याद आ रही है। यह इस बात का घोतक है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मृत परिस्थिति में है भाजपा के अस्तित्व को बचाने के लिये पूरी भाजपा का नेतृत्व प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में उतर आये है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद जनता को 15 साल बाद में एक विश्वसनीय सरकार मिली है जो उनके लिये न सिर्फ योजनाये बना रही है।

कांग्रेस राज में अपराधियों ने सारे रिकॉर्ड तोड़े : केदार

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने राजधानी में अपराधों के बढ़ते ग्राफ को लेकर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा है। श्री गुप्ता ने कहा कि अपराधियों ने राजधानी में कानून-व्यवस्था का मखौल उड़ा रखा है और यही स्थिति पूरे प्रदेश में हैं। चोरी, डाका, अपहरण हत्याएँ, चाकूबाजी, मारपीट, लूट, दुष्कर्म की बढ़ती वारदातों ने नागरिक सुरक्षा के तमाम सरकारी दावों की धज्जियाँ उड़ा दी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री गुप्ता ने कहा कि इस चालू वर्ष की पहली छमाही में ही हत्या के 33, हत्या के प्रयास के 41, चाकूबाजी के 47, बलात्कार के 91, और छेड़छाड़ के 79 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इस आशय का जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि मारपीट के 1,641 प्रकरण भी इस छमाही में दर्ज हुए हैं। बढ़ते अपराधों के चलते जब राजधानी में ही नागरिक सुरक्षा दाँव पर लगी हुई है, तो प्रदेश के दूरस्थ इलाकों की स्थिति का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। श्री गुप्ता ने कहा कि पुलिस द्वारा अपराधों में तुलनात्मक कमी आने का दावा करके अपनी पीठ थपथपाना बेहद शर्मनाक है, क्योंकि यह तो वे मामले हैं, जो पुलिस तक पहुँचे हैं। जो मामले जटिल कार्यप्रणाली के चलते पुलिस तक नहीं पहुँचते, उनकी गिनती कौन करेगा? राजधानी समेत प्रदेश के सभी इलाकों में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में कोताही किए जाने तक के कई मामले आए-दिन सामने आ रहे हैं।

प्रदेश में परीक्षा दर परीक्षा सामने आ रहा भर्ती घोटालाः चौधरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ में चल रहे भर्ती घोटाले और परीक्षा घोटाले पर भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में रोजगार में माफिया, भर्ती में माफिया, यह जो आशंकाएं हैं, वह परीक्षा दर परीक्षा बलवती होती जा रही हैं। अभी-अभी व्यापम ने सहायक शिक्षक के लिए मेरिट सूची जारी की। इस परीक्षा के लिए 10 जून 23 को जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें एक लाख 46 हजार 176 अभ्यर्थियों की उपस्थिति की बात कही गई थी। 2 जुलाई को जो परिणाम घोषित किया गया है उसमें अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट की जो संख्या है, वह 146275 है। 99 अभ्यर्थी अतिरिक्त कहां से आ गए। इसको लेकर सफाई के प्रेस नोट जारी किए गए हैं कि टेलीफोनिक आधार पर किया गया था। क्या पहले यह विज्ञप्ति जारी की गई थी कि टेलीफोनिक आधार पर अनुमानित उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या? ऐसा कुछ नहीं कहा गया। कभी इनके धावक हुसेन बोल्ड से ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ जाते हैं। उसमें लिपिकीय त्रुटि कह देते हैं। भर्ती में माफिया, रोजगार में माफिया की आशंका हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार बलवती होती जा रही है और छत्तीसगढ़ के युवाओं को अनेक प्रकार के अन्यायों का सामना करना पड़ रहा है जो अत्यंत दुर्भाग्य जनक है।

बैठक में शराब के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का आक्रोश

रायपुर । अवैध शराब बिक्री से त्रस्त ग्राम असौंदा के ग्रामीणों का आक्रोश इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति बनाने के लिये आयोजित बैठक में फूट पड़ा । इस आक्रोश को आसपास के ग्रामों के मौजूद उन ग्राम प्रमुखों का भी समर्थन मिला जिनके ग्राम के ग्रामीण यहां के सड़क मार्ग से गुजरते हैं और उन्हें इसकी वजह से अशोभनीय हरकतों का सामना करना पड़ता है । बैठक में असौंदा से लगे ग्राम मुड़पार व बिठिया में भी अवैध शराब बिक्री की बात सामने आयी । बैठक के तुरंत बाद असौंदा के महिलाओं व पुरुषों ने ग्राम प्रमुखों के साथ गांव के गली - कूचों में घूम इस अवैधानिक कृत्य में लिप्त तत्वों को इस अवैधानिक कृत्य से तौबा कर लेने की चेतावनी देते हुये ग्रामीण फरमान की अवहेलना करने पर ग्रामीण व्यवस्था के साथ - साथ प्रशासनिक कार्यवाही का भी सामना करने तैय्यार रहने के लिये आगाह किया। प्रतिदिन रैली निकाल चौकसी का भी निर्णय असौंदा के ग्रामीणों ने लिया है ।

ज्ञातव्य हो कि मंदिर हसौद से कोसरंगी व रायपुर से खरोरा सड़क मार्ग को जोड़ने वाली अमेरी से माठ सड़क पर पड़ने वाले ग्राम असौंदा में मुख्य सड़क मार्ग सहित ग्राम के भीतर जगह - जगह बिक रहे अवैध शराब की वजह से व्याप्त हो रहे अशांति से ग्रामीणों में गुस्सा व्याप्त तो था ही , इस मार्ग से गुजरने वाले आसपास के ग्रामीणों की परेशानियों को देख इन ग्रामों के ग्राम प्रमुखों ने भी असौंदा के पंचायत प्रतिनिधियों सहित ग्राम प्रमुखों पर भी अवैध शराब बिक्री रूकवाने लगातार दबाव बना रहे थे। इसी के परिप्रेक्ष्य में सरपंच राजेश साहू ने ग्रामीणों से मशविरा कर बीते रविवार को ग्रामवासियों सहित आसपास के ग्राम प्रमुखों की बैठक आहूत की थी। बैठक में असौंदा से वर्तमान सरपंच सहित पूर्व सरपंचद्वय जितेन्द्र चंद्राकर व राजू टंडन, जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष रहे मुरली वर्मा, उपसरपंच श्रीमती कुमारी बाई वर्मा, पंच देवनाथ वर्मा, पूर्णिमा साहू, पुष्पा वर्मा, ग्राम प्रमुख सुरेन्द्र चंद्राकर, रामकुमार साहू , कुमार यादव, मुरारी वर्मा, जितेन्द्र चेला, इतवारी चेलक, बद्री वर्मा, शिवकुमार वर्मा, लुकेश्वर पाल, महेश्वर साहू, बहादुर साहू, महेत्तर ध्रुव, नारायण वर्मा, चिंताराम सहित महिला स्व-सहायता समूह के महिलाओं सहित महिला प्रमुख गण व आमंत्रित किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा , क्षेत्रीय जनपद सदस्य सुरेन्द्र वर्मा , तुलसी के सरपंच प्रतिनिधि देवकुमार वर्मा, कठिया के सरपंच रुपेन्द्र वर्मा, सकरी के सरपंच प्रतिनिधि विक्की वर्मा, बिठिया के सरपंच बलराम साहू, बुड़ेनी के सरपंच जनकराम यदु, मुड़पार के सरपंच दिलीप पोर्ते मौजूद थे।

सभी जिला अस्पतालों में होगा डायलिसिस सुविधा का विस्तार : टीएस सिंहदेव

रायपुर। स्वास्थ्य सेवाओं के लगातार विस्तार से अब राज्य के 27 जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस की सुविधा विकसित कर ली गई है। इससे किडनी रोगों से पीड़ितों को अब उनके जिला मुख्यालय में ही निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। प्रदेश के दूरस्थ अंचलों के मरीजों को अब डायलिसिस के लिए बड़े शहरों का रूख नहीं करना पड़ रहा है। किडनी संबंधी रोग से ग्रस्त मरीज को लंबे समय तक बार-बार डायलिसिस कराना पड़ता है। इससे उन पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। स्थानीय स्तर पर ही निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिलने से अब इसके मरीजों को बड़ी राहत मिली है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव की पहल पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम 'जीवन धारा' और जिला खनिज न्यास निधि (छ्रस्न्न) से राज्य के 27 जिला मुख्यालयों तथा देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायलिसिस की सुविधा प्रारंभ की जा चुकी है। 'जीवन धारा' के अंतर्गत दुर्ग, कांकेर, बिलासपुर, महासमुंद, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, बीजापुर, रायपुर, जांजगीर, जगदलपुर, गरियाबंद, मुंगेली, धमतरी, बलौदाबाजार, बैकुंठपुर, सूरजपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही एवं सुकमा जिला चिकित्सालय तथा देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.